जनवरी 2024 ■ वर्ष : 33 ■ अंक : 5 ₹135

सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

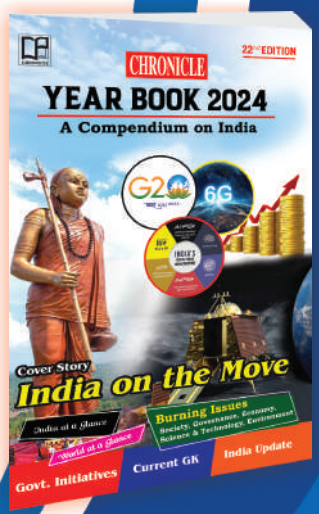

विशेषांक–4

सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण

भारतीय इतिहास एवं राजव्यवस्था

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु
50 अति महत्वपूर्ण विषयों की
परीक्षोपयोगी प्रस्तुति

अन्य आकर्षण

- न्यूज बुलेट्स
- चर्चित शब्दावली
- संसद प्रश्नोत्तरी
- समसामयिक प्रश्न
- PIB, AIR, PTI वनलाइनर
- पत्रिका सार : योजना, कुरुक्षेत्र एवं विज्ञान प्रगति (नवंबर 2023)
- परीक्षा सार : ओडिशा सिविल सेवा (OCS) प्रा. परीक्षा 2023 एवं संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) परीक्षा, 2023 पर आधारित
- फैक्ट शीट : बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी एवं भारत का पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र

विशेष आलेख

- भारत की उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां : एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन : व्यापक क्षमता एवं अपार आर्थिक संभावनाओं के अवसर
- पश्चिमी घाट का संकटग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र : वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट हेतु संरक्षण अनिवार्यताएं
- समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व : लाभ, चुनौतियां एवं समाधान
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना : महत्व एवं चुनौतियां
- डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 : उभरते मीडिया परिदृश्य के विनियमन हेतु महत्वपूर्ण

शीघ्र प्रकाश्य

समसामयिकी क्रॉनिकल

करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2024

दिसंबर 2023 तक अद्यतन

जनवरी 2024 सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल 1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

इस अंक में

www.chronicleindia.in
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका
facebook/civilserviceschronicle
जनवरी 2024
❑ वर्ष 33 ❑ अंक 5

59 सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-4
भारतीय इतिहास एवं राजव्यवस्था

सामयिक आलेख

06 भारत में उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां : एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता
09 पश्चिमी घाट का संकटग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र : वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए संरक्षण अनिवार्यताएं
12 भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन : व्यापक क्षमता एवं अपार आर्थिक संभावनाओं के अवसर

इन फोकस

15 डिजिटल विज्ञापन नीति 2023: उभरते मीडिया परिदृश्य के विनियमन हेतु महत्वपूर्ण
16 समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्व : लाभ, चुनौतियां एवं समाधान
17 डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना : महत्व एवं चुनौतियां

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय परिदृश्य......................................19-25
19 प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 का मसौदा
20 राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 का मसौदा
20 फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का विस्तार
21 चुनावी बांड योजना की वैधता
21 राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते : न्यायालय
22 सांसदों एवं विधायकों पर आपराधिक मुकदमा
22 पत्रकारों की डिजिटल गोपनीयता की रक्षा
22 भारत में सड़क दुर्घटनाएं : रिपोर्ट 2022
23 'शहरों के लिए AAINA डैशबोर्ड' पोर्टल
24 प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान
24 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को मंजूरी
25 मैतेई चरमपंथी संगठनों के विरुद्ध यूएपीए के तहत प्रतिबंध
25 गलत सूचना एवं डीफेक की पहचान हेतु परामर्श जारी

सामाजिक परिदृश्य........................ 26-28
26 सरोगेट मां को मातृत्व अवकाश
26 पीएम पीवीटीजी विकास मिशन
27 2024 एशिया-प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट
27 अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन
28 बच्चों को गोद लेने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान
28 विदेशी विश्वविद्यालय के संचालन संबंधी मसौदा नियम

विरासत एवं संस्कृति 29-32
29 जनजातीय लोक नायक बिरसा मुंडा की जयंती
29 गुरु नानक देव की 554वीं जयंती
30 आचार्य जे. बी. कृपलानी
30 तेलंगाना में जियोग्लिफ सर्कल
31 कंबाला महोत्सव
31 ओडिशा का बाली यात्रा उत्सव
31 छऊ लोक नृत्य
31 वांगला महोत्सव
32 बलबन का मकबरा

आर्थिक परिदृश्य 33-38
33 सतत व्यापार एवं मानकों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन
34 'रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन' (RISE) कार्यक्रम
34 'नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम' तथा 'एनर्जी एफिशिएंट फैन्स प्रोग्राम'
35 वर्ल्ड फूड इंडिया-2023
35 59वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक
36 वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत-2023
36 अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की 63वीं परिषद बैठक
37 बैंकों एवं NBFC के असुरक्षित ऋण पर जोखिम भार में वृद्धि
37 नाबार्ड तथा ICRIER द्वारा प्रकाशित शोध रिपोर्ट
38 सूचकांक प्रदाताओं हेतु एक नियामक ढांचे को मंजूरी

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन 39-44

39 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus)
39 भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता
40 विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन
40 2023 APEC आर्थिक नेताओं की बैठक
41 दूसरा वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन
41 भारत व अमेरिका के मध्य स्टार्टअप्स एवं नवाचार सहयोग समझौता
42 बांग्लादेश में भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
42 भूटान नरेश की भारत यात्रा
42 भारत-इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र
43 भारत-मलेशिया संयुक्त आयोग की छठी बैठक
43 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हिंसा से विस्थापन
43 द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (SoFA), 2023 रिपोर्ट
44 यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि का निलंबन
44 गाजा में 'मानवीय विराम' का संकल्प

पर्यावरण एवं जैव विविधता 45-52

45 CITES के स्थायी समिति की 77वीं बैठक
46 अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की बैठक
46 उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, 2023
47 जलवायु वित्त पर ओईसीडी की रिपोर्ट
47 अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023
47 उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2023
48 अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र
49 दिल्ली, कोलकाता व मुंबई विश्व के तीन सर्वाधिक प्रदूषित शहर
49 जैव विविधता टाइम मशीन
50 संपीडित बायोगैस का अनिवार्य सम्मिश्रण
51 सीबीएएम पर भारत-यूरोप में भिन्नता
51 प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष
52 सर्वाधिक गर्म 12 महीने

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 53-58

53 पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता
53 चिकनगुनिया वायरस के लिए विश्व के प्रथम टीके को मंजूरी
54 संशोधित एंटीफंगल एजेंट के रोगाणुरोधी गुण
54 खसरा और रूबेला वैक्सीन- 'माबेला'
55 चीन में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी में वृद्धि
55 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए जेनेरिक दवाएं
55 आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल
56 वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट-2023
56 बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय'
57 संचार उपग्रह, O3b mPOWER 5 और 6 का प्रक्षेपण
57 प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन
58 थ्रॉटल एयरोस्पेस को बहुउद्देश्यीय ड्रोन हेतु टाइप-प्रमाणन

प्रतियोगिता क्रॉनिकल

न्यूज बुलेट्स 111
चर्चित शब्दावली 129
राज्य परिदृश्य 131
खेल परिदृश्य 134
लघु संचिका 137
पत्रिका सार : योजना, कुरुक्षेत्र एवं विज्ञान प्रगति 140
संसद प्रश्नोत्तरी 147
परीक्षा सार 149
फैक्ट शीट 158
समसामयिक प्रश्न 159
वन लाइनर 161

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं इम्प्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नंबर C-18-19-20-21, सेक्टर-59, नोएडा-201301 से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

भारत में उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां

एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता

• डॉ. अमरजीत भार्गव

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत एक तरफ जहां तीव्र आर्थिक प्रगति के साथ वैश्विक कूटनीति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में आधुनिक प्रौद्योगिकियों के विस्तार के साथ विशिष्ट नवीन सुरक्षा चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार की सुरक्षा चुनौतियां केवल सैन्य और परमाणु हमलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें साइबर हमले, आतंकवाद की परिवर्तनशील प्रकृति तथा जनसांख्यिकीय परिवर्तन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। भारत के समक्ष उभरती नवीन सुरक्षा चुनौतियां व्यापक स्तर पर तैयारी एवं सक्रिय प्रतिक्रिया की मांग करती हैं।

वर्तमान समय में उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर विभिन्न सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा भारत में एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर प्रगति तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार जटिल होते भू-राजनीतिक परिदृश्य ने वर्तमान समय में नई राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दिया है। इन सुरक्षा चुनौतियों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संबंधित संस्थानों और राज्यों को विभिन्न दिशा-निर्देश और नियम जारी किए जाते रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान परिवर्तनशील तकनीकी युग में सरकार उभरती नवीन राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील है। परन्तु, नीतिगत समग्रता के अभाव में इस प्रकार के प्रयास व्यापक परिणाम उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा रहा है कि भारत को इन उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (National Security Strategy - NSS) का निर्माण करने की आवश्यकता है।

भारत के समक्ष प्रमुख उभरती सुरक्षा चुनौतियां

17 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बताया गया था कि 'सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं को मजबूत करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है'।

भूमि और समुद्री सीमाओं, वायु क्षेत्र, साइबर, डेटा, अंतरिक्ष, सूचना, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की सुरक्षा तथा एक संप्रभु राष्ट्र के लिए इन तत्वों की सुरक्षा करना आवश्यक है। भारत को घरेलू तथा बाह्य दोनों स्तरों पर अनेक राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना पड़ रहा है। कुछ प्रमुख उभरती चुनौतियां इस प्रकार हैं:

* **साइबर सुरक्षा:** प्रौद्योगिकी और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के साथ, साइबर सुरक्षा एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है। बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और बढ़ते आईटी क्षेत्र के कारण भारत साइबर हमलों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील गंतव्य स्थल के रूप में उभरा है।
  - डीप फेक (Deep Fake), रैंसमवेयर और मैलवेयर (Ransomware & Malware), फिशिंग हमले (Phishing Attacks), गलत सूचना एवं फेक न्यूज जैसी घटनाएं नवीन साइबर सुरक्षा चुनौतियों के रूप में उभरी हैं।
* **सीमा विवाद की परिवर्तनशील प्रकृति:** भारत स्वतंत्रता के बाद से ही पाकिस्तान एवं चीन के साथ सीमा विवादों का सामना कर रहा है।
  - हाल के वर्षों में नेपाल के साथ उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधूरा और लिपूलेख जैसे क्षेत्रों में उत्पन्न सीमा विवाद ने न केवल भारत की चिंताओं में वृद्धि की है, बल्कि पड़ोसी देशों में भारत की स्वीकार्यता भी प्रभावित हुई है।
  - अन्य नवीन प्रवृत्तियों में, चीन द्वारा म्यांमार तथा श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में की जा रही अपनी पहुंच में वृद्धि से भारत की सीमाएं अत्यधिक संवेदनशील हुई हैं।
* **आतंकवाद:** अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता तथा पाकिस्तान प्रेरित आतंकी घटनाओं के कारण भारत की सुरक्षा चुनौतियों में वृद्धि हुई है।
  - इस क्षेत्र में सक्रिय आतंकी संगठनों द्वारा आधुनिक कंप्यूटर एवं इंटरनेट तकनीकों (कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मशीन लर्निंग) तक पहुंच स्थापित करने के खतरों ने चिंताओं को और भी अधिक बढ़ा दिया है।
* **पंजाब में खालिस्तान-प्रेरित उग्रवाद:** पंजाब के अमृतसर में अजनाला पुलिस स्टेशन की हालिया घटना और पंजाब में खालिस्तान समर्थक भावनाओं में वृद्धि से 1980 के दशक के भयावह दौर की वापसी की व्यापक आशंकाएं बढ़ रही हैं, जब पाकिस्तान प्रायोजित विद्रोह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित किया था।
* **सीमाओं पर नशीली दवाओं की तस्करी:** चीन तथा पाकिस्तान के समर्थन से संगठित अपराध के सदस्यों या ड्रग डीलरों द्वारा देश की पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित एक स्पष्ट बाजार विकसित किया जा रहा है।
  - नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध हथियारों की आपूर्ति, मानव तस्करी तथा सीमा पर उग्रवादी घटनाओं में वृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यह देश की युवा आबादी को अनुत्पादक गतिविधियों की ओर भी ले जाती है।
  - दिसंबर 2022 में लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गांजा, हेरोइन तथा अफीम सहित 486.2 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे।

पश्चिमी घाट का संकटग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र

वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट हेतु संरक्षण अनिवार्यताएं

• संपादकीय डेस्क

पश्चिमी घाट के वनों, झीलों तथा नदियों का यहां की पारिस्थितिक विविधता को बनाए रखने में एक विशेष स्थान है। अतः इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक सेवाओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए एवं इन्हें सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली खनन तथा औद्योगिक गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

हाल ही में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT Bombay) द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि वर्ष 1990 से 2020 के बीच पश्चिमी घाट क्षेत्र (WGR) के मृदा अपरदन में 94% की बढ़ोतरी देखी गई है। मृदा अपरदन की यह प्रवृत्ति जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में इस क्षेत्र के लिए अत्यंत 'हानिकारक' (Detrimental) है।

- पश्चिमी घाट विश्व के 36 'जैव विविधता वाले तप्त स्थलों' की सूची में शामिल है। साथ ही, श्रीलंका के आर्द्र प्रदेशों के साथ भारत के पश्चिमी घाट को विश्व के 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण तप्त स्थलों में भी शामिल किया गया है। परंतु, अवसंरचनात्मक विकास संबंधी परियोजनाओं तथा खनन जैसी क्रियाओं में वृद्धि होने के कारण पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक असंतुलन से यहां की जैव विविधता पर संकट उत्पन्न हो गया है।
- सरकार की तरफ से इस संदर्भ में समय-समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं, किंतु अभी तक इसके संरक्षण की दिशा में किसी भी प्रकार की ठोस योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है। उपर्युक्त परिदृश्य में पश्चिमी घाट के महत्व तथा इसके संरक्षण के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण अतिआवश्यक है।

पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक सुभेद्यता/भंगुरता : उत्तरदायी कारक

- **खनन:** लौह अयस्क की कीमतों में भारी वृद्धि और निचले दर्जे के अयस्कों की मांग के कारण, खनन गतिविधियों में विशेषकर गोवा में तीव्र वृद्धि हुई है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय क्षति और गंभीर सामाजिक व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं।
  - इसी प्रकार, केरल में रेत खनन एक बड़े खतरे के रूप में उभरा है। निरंतर खनन से न केवल भूस्खलन, जल स्रोतों और कृषि के नुकसान की संभावना बढ़ गई है; बल्कि यह वहां रहने वाले लोगों की आजीविका को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है।
- **मृदा अपरदन:** पश्चिमी घाट में मृदा अपरदन को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों में स्थानांतरित कृषि तथा वायु अपरदन शामिल है। वायु अपरदन यहां मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में अधिक होता है, जहां विरल वनस्पतियां पाई जाती हैं और वे शुष्क या अर्ध-शुष्क जलवायु क्षेत्र में आते हैं।
- **वनों की कटाई:** पश्चिमी घाट के अनेक भागों में व्यावसायिक उद्देश्यों, पर्यटन को बढ़ावा देने तथा वन भूमि को कृषि भूमि में बदले जाने के कारण व्यापक स्तर पर वनों की कटाई की जा रही है, इससे यहां के पारितंत्र पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं।
- **पशुओं द्वारा चराई:** संरक्षित क्षेत्रों के आंतरिक हिस्सों में पशुओं (मवेशियों और बकरियों) का उच्च घनत्व एवं उनके द्वारा अत्यधिक चराई के कारण पश्चिमी घाट में स्थानीय जीवों के लिए आवास का संकट उत्पन्न हो गया है।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** मानवीय गतिविधियों के बढ़ने से पश्चिमी घाट में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक आम घटना के रूप में उभरा है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक राज्य में भद्रा वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास रहने वाले ग्रामीणों के वार्षिक अनाज उत्पादन का लगभग 11% प्रतिवर्ष हाथियों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है।
- **वनोपज का निष्कर्षण:** पश्चिमी घाट में संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और आस-पास रहने वाले मानव समुदाय, निर्वाह और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ हद तक गैर-इमारती लकड़ी के रूप में वनोत्पादों के निष्कर्षण पर निर्भर हैं।
- **व्यावसायिक वृक्षारोपण:** निजी व्यक्तियों और कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले वृक्षारोपण की पश्चिमी घाट में वृद्धि हुई है। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले इस प्रकार के वृक्षारोपण में केवल विशिष्ट और एकल प्रकार की वनस्पतियों को उगाया जाता है; इसने प्राकृतिक आवास के विखंडन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **मानव बस्तियों द्वारा अतिक्रमण:** कानूनी मान्यता प्राप्त अथवा परंपरागत अधिकारों के तहत निर्मित मानव आवासों की संरक्षित क्षेत्रों के आंतरिक एवं बाहरी दोनों भागों में वृद्धि देखने को मिल रही है। भू-माफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण के साथ पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि इस संदर्भ में महत्वपूर्ण समस्या बनकर उभरी है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप यहां के कुछ राज्य (विशेषकर केरल एवं महाराष्ट्र) पिछले कुछ वर्षों से भारी बारिश के कारण भीषण बाढ़ तथा भूस्खलन जैसी घटनाओं का सामना कर रहे हैं।
- **प्रदूषण:** खनन संबंधी गतिविधियों के साथ वनों के आस-पास के क्षेत्रों में अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए चाय और कॉफी बागानों में एग्रोकेमिकल्स का अप्रतिबंधित उपयोग, पश्चिमी घाट के जलीय और वन पारिस्थितिक प्रणालियों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है।
- **जलविद्युत परियोजनाएं एवं बड़े बांध:** सरकार तथा विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययनों में यह देखा गया है कि पश्चिमी घाट में बड़े बांध परियोजनाओं की उपस्थिति से अनेक पर्यावरणीय एवं सामाजिक व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं।
- **भू-जल संकट:** विशिष्ट प्रकार की भौमिकीय संरचना के कारण पश्चिमी घाट में भूजल का स्तर अत्यंत निम्न है; आधुनिक उद्योगों तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के परिणामस्वरूप भूजल के स्तर में और भी अधिक गिरावट आने वाले समय में इस संपूर्ण क्षेत्र को गंभीर संकट में डाल सकती है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन

व्यापक क्षमता एवं अपार आर्थिक संभावनाओं के अवसर

• महेंद्र चिलकोटी

भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विश्व के सबसे व्यापक तथा सर्वाधिक विविधतापूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक का योगदान देता है तथा 4.4 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यह आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख चालक है; इसीलिये सरकार ने इसे विकास के एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है।

3 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2023' के द्वितीय संस्करण के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सनराइज उद्योग के रूप में उभरा है तथा इसने पिछले 9 वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 50,000 करोड़ रुपये आकर्षित किए हैं।

* वर्ल्ड फूड इंडिया भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। यह आयोजन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यवसायों को अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने, संभावित भागीदारों के साथ नेटवर्क बनाने तथा भारत के बढ़ते खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

* **रोजगार सृजन:** यह क्षेत्र रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो पंजीकृत विनिर्माण कार्यबल के लगभग 12.2% को रोजगार प्रदान करता है।
  - यह अकुशल श्रम से लेकर उच्च कुशल पेशेवरों तक, विभिन्न कौशल स्तरों पर रोजगार के अवसर सृजित करता है।
* **कृषि में मूल्यवर्धन:** खाद्य प्रसंस्करण कृषि उपज में मूल्य-वर्धन करता है; फसल पश्चात नुकसान को कम करता है तथा किसानों की आय में वृद्धि करता है। यह खराब होने वाले उत्पादों की उपयोग अवधि में वृद्धि करता है, बेहतर भंडारण और परिवहन को सक्षम बनाता है, जिससे बर्बादी कम होती है।
* **निर्यात को प्रोत्साहन:** भारत प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है, जो मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। वित्त वर्ष 2022-23 में, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का देश का निर्यात 19.69 बिलियन डॉलर था, जो इस क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।
* **आर्थिक विकास:** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारत के कुल निर्यात में लगभग 13% और औद्योगिक निवेश में 6% का योगदान देता है। यह आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृषि आजीविका का एक प्राथमिक स्रोत है।
* **बुनियादी ढांचे का विकास:** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि कोल्ड चेन, भंडारण सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क सहित बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करती है। ये सुविधाएं आपूर्ति शृंखला की दक्षता को बढ़ाती हैं और फसल पश्चात् होने वाले नुकसान को कम करती हैं।
* **पोषण सुरक्षा:** यह क्षेत्र विशेषकर ताजा उपज तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाकर, पोषण सुरक्षा में सुधार करने में योगदान देता है।
* **उद्यमशीलता के अवसर:** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विशेषकर लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए, उद्यमशीलता के कई अवसर प्रस्तुत करता है।
  - सरकारी पहल, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY), इस क्षेत्र में लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के विकास का समर्थन करती है।
* **भोजन की बर्बादी को कम करना:** कच्चे कृषि उत्पादों को मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करके, खाद्य प्रसंस्करण भोजन की बर्बादी को कम करने में सहायता मिलती है।
  - कुशल प्रसंस्करण और संरक्षण तकनीकों से भोजन की बर्बादी कम होगी, संसाधनों का संरक्षण होगा और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
* **कृषि आय का विविधीकरण:** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विस्तार कृषि उपज के लिए नए बाजार निर्मित करता है, जिससे किसानों को अपने आय स्रोतों में विविधता लाने और सीमित फसलों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।
* **खाद्य सुरक्षा में वृद्धि:** खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठान कड़े गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं, खाद्य उत्पादों की संपूर्णता सुनिश्चित करते हैं और उपभोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र : विकास के उत्प्रेरक कारक

भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में विभिन्न कारक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं; जो निम्नलिखित हैं-

* **प्रसंस्कृत खाद्य की बढ़ती मांग:** बदलती जीवनशैली, शहरीकरण तथा बढ़ती प्रयोज्य आय के कारण प्रसंस्कृत एवं पैकेज्ड खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ रही है।

in फोकस

- डिजिटल विज्ञापन नीति 2023: उभरते मीडिया परिदृश्य के विनियमन हेतु महत्वपूर्ण
- समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्व : लाभ, चुनौतियां एवं समाधान
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना : महत्व एवं चुनौतियां

डिजिटल विज्ञापन नीति 2023

उभरते मीडिया परिदृश्य के विनियमन हेतु महत्वपूर्ण

10 नवंबर, 2023 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्र सरकार की विज्ञापन शाखा केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए 'डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023' (Digital Advertisement Policy, 2023) को मंजूरी दी।

- डिजिटल विज्ञापन एक मार्केटिंग रणनीति है, जिसमें किसी कंपनी के ब्रांड और उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वेबसाइटों, सोशल मीडिया, सर्च इंजन आदि जैसे ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से विज्ञापन लॉन्च करना शामिल है।
- इंटरनेट की पहुंच में तीव्र वृद्धि वाले वर्तमान युग में उभरते मीडिया परिदृश्य के विनियमन की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में 'डिजिटल विज्ञापन नीति-2023' के महत्व पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

भारत में डिजिटल मीडिया के उपयोग की स्थिति

- भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के परिणामस्वरूप, देश भर में इंटरनेट, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है।
- ट्राई (TRAI) के 'भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक' (Indian Telecom Services Performance Indicator) जनवरी-मार्च 2023 के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच 880 मिलियन से अधिक तथा दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1172 मिलियन से अधिक दर्ज की गई थी।
- हाल के वर्षों में दर्शकों द्वारा किये जाने वाले मीडिया उपयोग को देखते हुए डिजिटल विज्ञापन नीति-2023 एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को प्रदर्शित करती है।

डिजिटल विज्ञापन नीति–2023 के महत्वपूर्ण बिंदु

- यह नीति वेबसाइटों, ओटीटी और पॉडकास्ट (OTT and Podcast) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू होगी। नीति केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) को OTT और 'वीडियो ऑन डिमांड' स्पेस में एजेंसियों और संगठनों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाएगी।
- इससे केंद्रीय संचार ब्यूरो, सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिटल मीडिया स्पेस का लाभ उठाने में सक्षम होगा।
- इस नीति के तहत, सरकार की डिजिटल पहुंच का दायरा बढ़ेगा और नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के तंत्र में सुधार होगा।
- यह नीति डिजिटल परिदृश्य की गतिशील स्थिति को समझते हुए CBC को विधिवत गठित समिति की स्वीकृति के साथ डिजिटल स्पेस में नए और अभिनव संचार प्लेटफार्मों में शामिल होने का अधिकार प्रदान करती है।
- CBC की डिजिटल विज्ञापन नीति-2023, पारदर्शिता और दक्षता को सुनिश्चित करने के साथ लागत के लिए प्रतिस्पर्धी बोली जैसी विशेषता भी प्रदान करती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित की गई दरें तीन वर्ष तक वैध रहेंगी और सभी पात्र एजेंसियों पर लागू होंगी।
- केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियानों का संचालन करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विज्ञापन विंग है।
  - यह 'सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय' के अंतर्गत कार्य का संचालन करता है और भारत में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जानकारी प्रसारित करने का दायित्व संभालता है।
  - CBC बदलते मीडिया परिदृश्य को अपनाने और व्यापक दर्शकों तक पहुंच बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 का महत्व

- यह नीति भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी के प्रसारण एवं जागरूकता उत्पन्न करने के CBC के मिशन के अनुरूप है।
- नीति द्वारा प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश विकल्पों के साथ लक्षित नागरिक केंद्रित संदेशों को प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे जन-आकांक्षी कार्यक्रमों को लागत दक्षता के साथ संचालित किया जा सकेगा।
- यह नीति उभरते मीडिया परिदृश्य तथा डिजिटल मीडिया के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए विशाल ग्राहक (Subscriber) आधार को केंद्र में रखकर निर्मित की गई है।

भारत में डिजिटल विज्ञापन राजस्व

- ऑनलाइन आंकड़ों के प्रमुख संग्रह statista.com के अनुसार वर्ष 2022 तक संपूर्ण भारत में डिजिटल विज्ञापन से उत्पन्न राजस्व का मूल्य लगभग 499 बिलियन भारतीय रुपये था।
  - उसी वर्ष, भारत का कुल विज्ञापन राजस्व एक ट्रिलियन भारतीय रुपये से अधिक था और विज्ञापन खर्च के मामले में भारत को दुनिया भर के सबसे बड़े विज्ञापन बाजारों में स्थान दिया गया था।

राजव्यवस्था

- प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 का मसौदा
- राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 का मसौदा
- फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का विस्तार

न्यायपालिका

- चुनावी बांड योजना की वैधता
- राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते : न्यायालय
- सांसदों एवं विधायकों पर आपराधिक मुकदमा
- पत्रकारों की डिजिटल गोपनीयता की रक्षा

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- भारत में सड़क दुर्घटनाएं : रिपोर्ट 2022

कार्यक्रम एवं पहल

- 'शहरों के लिए AAINA डैशबोर्ड' पोर्टल
- प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान

समिति एवं आयोग

- 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को मंजूरी

राष्ट्रीय सुरक्षा

- मैतेई चरमपंथी संगठनों के विरुद्ध यूएपीए के तहत प्रतिबंध
- गलत सूचना एवं डीपफेक की पहचान हेतु परामर्श जारी

राजव्यवस्था

प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 का मसौदा

10 नवंबर, 2023 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 'प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023' का मसौदा [Draft Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023] जारी किया, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए एक नये नियामक ढांचे का निर्माण करना है।

- मसौदा विधेयक देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक समेकित प्रारूप का प्रावधान करने के साथ-साथ मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में बदलाव लाने का प्रयास करता है।
- यह विधेयक नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ ओवर-द-टॉप (OTT) कंटेंट एवं डिजिटल समाचारों को कवर करने के लिए इसके दायरे का विस्तार करता है तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए समकालीन परिभाषाओं एवं प्रावधानों को प्रस्तुत करता है।

विधेयक की आवश्यकता

- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 तीन दशकों से प्रभावी है। यह केबल नेटवर्क सहित सीधे प्रसारण (Linear Broadcasting) की विषय-वस्तु की निगरानी करने वाले प्राथमिक कानून के रूप में कार्य कर रहा है।
- हालांकि, इस बीच प्रसारण परिदृश्य में तकनीकी प्रगति ने डीटीएच (DTH), आईपीटीवी (IPTV), ओटीटी (OTT) तथा विभिन्न एकीकृत मॉडल जैसे नए प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किए हैं।
- प्रसारण क्षेत्र के डिजिटलीकरण के साथ, विशेष रूप से केबल टीवी में, नियामक प्रारूप को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। इसमें अधिक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए, वर्तमान स्वरूप के नियामक प्रारूप को एक नए, व्यापक कानून से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।

मुख्य विशेषताएं

- **समेकन और आधुनिकीकरण:** यह विभिन्न प्रसारण सेवाओं के लिए विनियामक प्रावधानों को एकल विधायी ढांचे के तहत समेकित और अद्यतन करने की चिरकालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह वर्तमान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 से विनियमित ओवर-द-टॉप (OTT) कंटेंट और डिजिटल समाचार एवं सामयिक मामलों के प्रसारण को शामिल करने के लिए अपने विनियामक दायरे का विस्तार करता है।
- **समसामयिक परिभाषाएं और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रावधान:** उभरती प्रौद्योगिकियों एवं सेवाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए यह विधेयक समसामयिक प्रसारण शब्दावलियों के लिए व्यापक परिभाषाएं प्रस्तुत करता है और साथ ही उभरती प्रसारण प्रौद्योगिकियों के प्रावधानों को शामिल करता है।
- **स्व-नियमन व्यवस्था को मजबूत बनाना:** यह कंटेंट मूल्यांकन समितियों (Content Evaluation Committees) की शुरुआत के साथ स्व-नियमन को बढ़ावा देता है और साथ ही मौजूदा अंतर-विभागीय समिति को अधिक सहभागी और व्यापक 'प्रसारण सलाहकार परिषद' (Broadcast Advisory Council) में विकसित करता है।
- **पृथक कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता:** यह विभिन्न सेवाओं में कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के लिए पृथक दृष्टिकोण की अनुमति देता है तथा प्रतिबंधित कंटेंट के लिए प्रसारकों द्वारा स्व-वर्गीकरण और मजबूत पहुंच नियंत्रण उपायों को आवश्यक बनाता है।
- **दिव्यांगों के लिए पहुंच:** यह विधेयक व्यापक पहुंच दिशा-निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करते हुए दिव्यांगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
- **वैधानिक दंड एवं जुर्माना:** इस मसौदा विधेयक में ऑपरेटरों और प्रसारकों के लिए सलाह, चेतावनी, निंदा या मौद्रिक दंड जैसे वैधानिक दंड का समावेशन है। इसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान पहले की तरह जारी है, लेकिन यह केवल बेहद गंभीर अपराधों के लिए ही है, ताकि विनियमन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।

सामाजिक परिदृश्य

सामाजिक न्याय
- सरोगेट मां को मातृत्व अवकाश

कार्यक्रम एवं पहल
- पीएम पीवीटीजी विकास मिशन

रिपोर्ट एवं सूचकांक
- 2024 एशिया-प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट

बैठक एवं सम्मेलन
- अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन

अतिसंवेदनशील वर्ग
- बच्चों को गोद लेने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान

शिक्षा एवं स्वास्थ्य
- विदेशी विश्वविद्यालय के संचालन संबंधी मसौदा नियम

सामाजिक न्याय

सरोगेट मां को मातृत्व अवकाश

हाल ही में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि सरोगेसी (Surrogacy) की प्रक्रिया से बच्चे को जन्म देने वाली मां को मातृत्व अवकाश देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

- अदालत ने **राज्य सरकार के 23 जून, 2020 के उस आदेश को रद्द कर** दिया, जिसके तहत सरोगेसी से बच्चा जन्म देने वाली याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि सरोगेट माताओं को मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने का अर्थ भारत के संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा।
- अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मातृत्व का अधिकार और प्रत्येक बच्चे के पूर्ण विकास का अधिकार भी शामिल है।
- **सरोगेसी** एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें एक महिला (सरोगेट) किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े (इच्छित माता-पिता) की ओर से बच्चे को जन्म देने के लिये सहमत होती है। कभी-कभी सरोगेट महिला को **गर्भकालीन वाहक** भी कहा जाता है।
- **सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021** के अनुसार 35 से 45 वर्ष आयु की विधवा या तलाकशुदा महिला या कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष के रूप में परिभाषित युगल सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं, यदि उनके पास इस विकल्प की आवश्यकता वाली कोई चिकित्सीय स्थिति है।
- अधिनियम के तहत **वाणिज्यिक सरोगेसी प्रतिबंधित** है। इसका उल्लंघन करने पर 10 वर्ष कारावास तथा 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  - यह कानून **केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति** देता है, जहां कोई पैसे का आदान-प्रदान नहीं होता, साथ ही यह भी आवश्यक है कि सरोगेट मां आनुवंशिक रूप से बच्चे की तलाश करने वालों से संबंधित होनी चाहिये।
- **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961** गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के रोजगार का समर्थन करता है। यह महिला कर्मचारी को 'मातृत्व लाभ' की गारंटी देता है। 10 से अधिक कर्मचारियों वाली किसी भी व्यावसायिक इकाई को इस नियम का पालन करना होता है।
- **मातृत्व संशोधन अधिनियम, 2017** के तहत मातृत्व अवकाश को **12 सप्ताह से बढ़ाकर 26** सप्ताह कर दिया गया है। मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत किये गए संशोधनों में 26 सप्ताह के **सवेतनिक प्रसूति अवकाश** के साथ-साथ **अनिवार्य क्रैच सुविधा** का विशेष प्रावधान किया गया है।

कार्यक्रम एवं पहल

पीएम पीवीटीजी विकास मिशन

15 नवंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 28 लाख आदिवासी आबादी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए ₹24,000 करोड़ की योजना 'पीएम पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) विकास मिशन' [PM PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Groups) Development Mission] का शुभारंभ किया।

- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने **'विकसित भारत संकल्प यात्रा'** (Viksit Bharat Sankalp Yatra) का भी शुभारंभ किया, और इस यात्रा के शुभारंभ को चिह्नित करते हुए, झारखंड के खूंटी में **'आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) वैन'** [IEC (Information, Education and Communication) Vans] को हरी झंडी दिखाई।

मिशन के संदर्भ में

- इस मिशन को **केंद्रीय बजट 2023-24** में सूचीबद्ध 7 सप्तर्षि प्राथमिकताओं में से एक, **'रीचिंग द लास्ट माइल'** के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है।
- यह मिशन देश भर में 75 पीवीटीजी की समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भारत के **18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश** (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) में रहते हैं।

विरासत एवं संस्कृति

- गुरु नानक देव की 554वीं जयंती
- आचार्य जे. बी. कृपलानी

पुरातात्विक साक्ष्य

- तेलंगाना में जियोग्लिफ सर्कल

उत्सव एवं पर्व

- कंबाला महोत्सव
- ओडिशा का बाली यात्रा उत्सव
- छऊ लोक नृत्य
- वांगला महोत्सव

विरासत स्थल एवं स्मारक

- बलबन का मकबरा

व्यक्तित्व

- जनजातीय लोक नायक बिरसा मुंडा की जयंती

व्यक्तित्व

जनजातीय लोक नायक बिरसा मुंडा की जयंती

15 नवंबर, 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है।

- सरकार ने बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' मनाए जाने की घोषणा 10 नवंबर, 2021 को की थी। बिरसा मुंडा को देश भर के जनजातीय समुदायों द्वारा भगवान के रूप में सम्मान दिया जाता है।
- इनका जन्म 15 नवंबर, 1875 को तत्कालीन बंगाल प्रेसीडेंसी के लोहरदगा जिले के उलिहातु गांव (जो वर्तमान में झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है) में हुआ था। बिरसा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में प्राप्त की।

योगदान

- **समाज सुधार:** बिरसा मुंडा ने नैतिक आचरण की शुद्धता एवं आत्मसुधार पर बल दिया। उन्होंने जनजातियों को अंधविश्वास की जकड़न से निकालने का भी प्रयास किया।
  - उन्होंने जनजातियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझने और एकता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया।
  - झारखंड तथा आस-पास के क्षेत्र के मुंडा आदिवासी आज भी उन्हें 'धरती आबा' (Father of Earth) कहते हैं।
- **स्वतंत्रता संग्राम:** बिरसा मुंडा ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ थे। विरोध करने के कारण इन्हें 24 अगस्त, 1895 को गिरफ्तार कर लिया गया तथा दो साल की कैद की सजा सुनाई गई।
  - इनके नेतृत्व में 1899-1900 के दौरान मुंडा विद्रोह 'उलगुलान' (Great Tumult) की शुरुआत हुई। विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशनों, सार्वजनिक संपत्तियों, चर्चों तथा जमीदारों को निशाना बनाया। 9 जून, 1900 को बिरसा मुंडा की जेल में हैजा होने से मृत्यु हो गई।
- **धार्मिक योगदान:** बिरसा ने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को अनेक देवी-देवताओं को छोड़कर एक ईश्वर की आराधना करने का उपदेश दिया।
- **राजनीतिक:** बिरसा ने ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चता को अस्वीकार किया तथा अपने अनुयायियों को सरकार को टैक्स या लगान न देने के लिए प्रेरित किया। उन्हें जनजातीय समुदाय को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लामबंद करने के लिए जाना जाता है।

गुरु नानक देव की 554वीं जयंती

27 नवंबर, 2023 को विश्व भर में गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती मनाई गई। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और दस सिख गुरुओं में से पहले हैं। गुरु नानक जयंती को प्रकाश उत्सव या गुरु पूरब के नाम से भी जाना जाता है।

संक्षिप्त परिचय

- **जन्म:** इनका जन्म 1469 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर के निकट ननकाना साहिब में हुआ था। ननकाना साहिब को पहले 'राय-भोई-दी-तलवंडी' के नाम से जाना जाता था।
- **माता-पिता:** गुरु नानक देव जी, सिखों के 10 गुरुओं में से पहले हैं। उनके पिता का नाम मेहता कालू जी और माता का नाम तृप्ता था।
- **समकालीन शासक:** वह मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे।

प्रमुख शिक्षाएं

- **समानता और सामाजिक न्याय:** गुरु नानक ने सामाजिक समानता की पुरजोर वकालत की, जाति-आधारित भेदभाव को खारिज किया और इस विचार को बढ़ावा दिया कि सभी व्यक्ति समान हैं।
- **मानवता की सेवा:** 'सेवा' या निस्वार्थ सेवा की अवधारणा सिख धर्म का केंद्र है। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को मानवता के प्रति दयालुता और सेवा के कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया।
- **आजीविका का उचित साधन:** गुरु नानक ने कड़ी मेहनत और नैतिक तरीकों से आजीविका कमाने के महत्व पर जोर दिया।
- **मानवता की एकता :** गुरु नानक ने 'मानवता की एकता की शिक्षा दी। गुरु नानक ने कहा कि "अपने अंदर प्रभु के प्रकाश

व्यापार एवं निवेश

- सतत व्यापार एवं मानकों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन

कार्यक्रम एवं पहल

- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'लीप अहेड' पहल
- 'रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन' (RISE) कार्यक्रम
- 'नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम' तथा 'एनर्जी एफिशिएंट फैन्स प्रोग्राम'

बैठक एवं सम्मेलन

- वर्ल्ड फूड इंडिया-2023
- 59वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक
- वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत-2023
- अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की 63वीं परिषद बैठक

मुद्रा एवं बैंकिंग

- बैंकों एवं NBFC के असुरक्षित ऋण पर जोखिम भार में वृद्धि

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- नाबार्ड तथा ICRIER द्वारा प्रकाशित शोध रिपोर्ट

वित्त क्षेत्र

- सूचकांक प्रदाताओं हेतु एक नियामक ढांचे को मंजूरी

व्यापार एवं निवेश

सतत व्यापार एवं मानकों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन

2-3 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में **'सतत व्यापार एवं मानकों (ICSTS) पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन'** का आयोजन किया गया।

- इस सम्मेलन को 'स्थिरता मानकों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम' (UNFSS) के सहयोग से **'उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग'** (DPIIT) के एक स्वायत्त संगठन- **'क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया'** (QCI) की मेजबानी में आयोजित किया गया था।
- सम्मेलन को आयोजित करने के **उद्देश्यों में**- व्यापार संबंधों को मजबूत करना, मानकों में सामंजस्य स्थापित करना तथा हितधारकों के बीच स्वैच्छिक स्थिरता मानकों (Voluntary Sustainability Standards-VSS) में सुधार करना शामिल थे।
- इस सम्मेलन में व्यापार संबंधों को मजबूत करने और मानकों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए QCI और **अफ्रीकी क्षेत्रीय मानक संगठन** (ARSO) के बीच एक **द्विपक्षीय समझौता हुआ**, इस समझौते से वैश्विक व्यापार परिदृश्य बेहतर होगा।
- सम्मेलन के दौरान **'राष्ट्रीय तकनीकी कार्य समूह'** (NTWG) व्यवस्था के माध्यम से **ग्लोबल जी.ए.पी.** (GLOBAL G.A.P.) द्वारा **इंडजी एपी की बेंचमार्किंग** (Benchmarking of IndG-AP) और **'राष्ट्रीय व्याख्या दिशा-निर्देशों'** (National Interpretation Guidelines-NIG) का सृजन भी हुआ, इससे लगभग 12,000 किसानों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
  - ग्लोबल जीएपी (Good Agricultural Practices-GAP) अच्छी कृषि पद्धतियों के लिए समर्पित कृषि मानकों का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन है।
  - वहीं इंडिया गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज (IndG.A.P.) भारतीय गुणवत्ता परिषद की एक प्रमाणन योजना है।
- आपसी सहभागिता को जारी रखते हुए **भारत ने 'स्थिरता मानकों पर सहयोग'** (Voluntary Sustainability Standards) के लिए **ब्राजील, मेक्सिको और अफ्रीकी क्षेत्रीय मानक संगठन** (ARSO) के साथ **समझौते** पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **ओएनडीसी** (Open Network for Digital Commerce-ONDC) के विक्रेता ऐप पर निर्बाध रूप से संस्थाओं को शामिल करने के लिए उनकी डिजिटल तैयारी का आकलन करने की जिम्मेदारी ओएनडीसी द्वारा भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) को दी गई है।
- ओएनडीसी की **डिजिटलीकरण पहल, ई-कॉमर्स** क्रांति को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप होगी, जिससे डिजिटल युग में व्यापार और भी अधिक सुलभ, पारदर्शी एवं बेहतर हो जाएगा।
  - **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स** (ONDC) एक सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसे भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा एक निजी गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।
  - **ONDC का उद्देश्य** डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है।
  - यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) की तरह काम करता है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)

- वर्ष 1996 में QCI को एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- QCI की स्थापना PPP मॉडल के माध्यम से एक 'स्वतंत्र स्वायत्त संगठन' के रूप में भारत सरकार और निम्नलिखित तीन प्रमुख उद्योग संघों द्वारा की गई थी-
  - एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM)
  - भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), फिक्की (FICCI)
- QCI के संचालन हेतु नोडल एजेंसी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत 'औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग' है।

बैठक एवं सम्मेलन

- 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus)
- भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता
- विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन
- 2023 APEC आर्थिक नेताओं की बैठक
- दूसरा वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन

द्विपक्षीय-संबंध

- भारत व अमेरिका के मध्य स्टार्टअप्स एवं नवाचार सहयोग समझौता
- बांग्लादेश में भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
- भूटान नरेश की भारत यात्रा
- भारत-इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र
- भारत-मलेशिया संयुक्त आयोग की छठी बैठक

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हिंसा से विस्थापन

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (SoFA), 2023 रिपोर्ट

संधि एवं समझौते

- यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि का निलंबन
- गाजा में 'मानवीय विराम' का संकल्प

बैठक एवं सम्मेलन

10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus)

16-17 नवंबर, 2023 के मध्य भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जकार्ता, इंडोनेशिया में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus) में भाग लिया। इंडोनेशिया एडीएमएम-प्लस का वर्तमान अध्यक्ष है।

- एडीएमएम-प्लस (ADMM-Plus) 10 आसियान सदस्य देशों एवं 8 संवाद भागीदार देशों के मध्य **सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक मंच** है।
- **8 संवाद भागीदार देशों में**- भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
  - **भारत 1992** में आसियान का संवाद भागीदार देश बना था।
- **आसियान के 10 देशों में** ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है।
- बैठक में भारत ने **आसियान की केंद्रीय भूमिका के महत्त्व की पुष्टि** की तथा क्षेत्र में वार्ता एवं आम सहमति को बढ़ावा देने में आसियान के प्रयासों की सराहना की।
- भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों, विशेष रूप से **'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS)-1982'** के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में नेविगेशन तथा वैध वाणिज्यक गतिविधियों की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- एडीएमएम-प्लस **7 विशेषज्ञ कार्य समूहों (EWG)** [समुद्री सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा, साइबर सुरक्षा, शांति स्थापना गतिविधि, आतंकवाद विरोधी प्रयास, मानव को बारूदी सुरंग से बचाने की कार्रवाई और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR)] के माध्यम से सदस्य देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाता है।
- इस दौरान, भारत ने **'आतंकवाद-निरोध पर EWG'** की सह-अध्यक्षता करने का प्रस्ताव रखा। आतंकवाद के गंभीर खतरों को देखते हुए इसे एडीएमएम-प्लस द्वारा स्वीकृत चिंता के प्रमुख विषयों में शामिल किया गया है।
- **भारत** वर्तमान समय (2021-2024) में इंडोनेशिया के साथ **'HADR पर EWG' की सह-अध्यक्षता** कर रहा है।
- **प्रथम ADMM-प्लस** का आयोजन वर्ष **2010 में हनोई, वियतनाम** में हुआ था। ADMM आसियान में सर्वोच्च रक्षा सलाहकार व सहकारी तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- वर्ष **2017 के बाद से ADMM-प्लस की बैठक वार्षिक रूप में** आयोजित की जाती है, ताकि चुनौतीपूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल के मध्य आसियान तथा प्लस देशों के बीच बातचीत एवं सहयोग बढ़ाया जा सके।

भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता

20 नवंबर, 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने एवं महत्वपूर्ण खनिजों तथा व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के लिए नई दिल्ली में 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता (2+2 Ministerial Dialogue) आयोजित की।

- इस वार्ता की **सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर** ने की।
- ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों में **उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मामलों की मंत्री पेनी वोंग** शामिल रहे।
- इससे पूर्व, **सितंबर 2021** में नई दिल्ली में **प्रथम 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता** हुई थी। जून 2020 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए **'म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट'** (Mutual Logistics Support Agreement: MLSA) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

पर्यावरण एवं जैव विविधता

बैठक एवं सम्मेलन

- CITES के स्थायी समिति की 77वीं बैठक
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधान (ISA) की बैठक

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, 2023
- जलवायु वित्त पर ओईसीडी की रिपोर्ट
- अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023
- उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2023

पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण

- अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र
- दिल्ली, कोलकाता व मुंबई विश्व के तीन सर्वाधिक प्रदूषित शहर

जैव विविधता

- जैव विविधता टाइम मशीन

ऊर्जा एवं सतत विकास

- संपीड़ित बायोगैस का अनिवार्य सम्मिश्रण

वन्यजीव संरक्षण

- प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष

जलवायु परिवर्तन

- सर्वाधिक गर्म 12 महीने

बैठक एवं सम्मेलन

CITES के स्थायी समिति की 77वीं बैठक

6–10 नवंबर, 2023 के दौरान स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 'वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन' (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora - CITES) की स्थायी समिति की 77वीं बैठक आयोजित की गई।

बैठक के मुख्य बिंदु

- **भारत एवं रेड सैंडर्स का व्यापार:** भारत को रेड सैंडर्स (Red sanders) के लिए CITES की महत्वपूर्ण व्यापार समीक्षा (Review of Significant Trade - RST) से हटा दिया गया है।
  - CITES की महत्वपूर्ण व्यापार समीक्षा (RST) एक प्रबंधन प्रणाली है, जिसके माध्यम से CITES स्थायी समिति किसी देश से किसी प्रजाति के निर्यात पर जाँच करती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कन्वेंशन ठीक से लागू किया जा रहा है या नहीं।
  - भारत, वर्ष 2004 से रेड सैंडर्स के लिये महत्त्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा (RST) प्रक्रिया के अधीन था।
- **भारत की श्रेणी:** इस बैठक में भारत को CITES के राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम (CITES National Legislation programme) की श्रेणी 1 में रखने का निर्णय लिया गया, क्योंकि भारत ने वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के द्वारा CITES के विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया है।
  - CITES प्रावधान करता है कि प्रत्येक पक्षकार CITES प्रावधानों को समायोजित करने के लिये अपने राष्ट्रीय कानून को संरेखित करें। इसके पूर्व भारत को CITES राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम के लिये श्रेणी 2 में सूचीबद्ध किया गया था।

लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)

- यह देशों के बीच बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय समझौता (संधि) है, जिसे 1963 में IUCN के सदस्यों द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था। 1975 में यह लागू हुआ।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा न हो।
- इसके अंतर्गत वर्तमान में जानवरों और पौधों की 37,000 से अधिक प्रजातियों की अलग-अलग श्रेणियों को विभिन्न परिशिष्टों में रखकर सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- CITES सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी (legally binding) है। हालांकि यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता है। भारत इसका एक हस्ताक्षरकर्ता है और 1976 में CITES कन्वेंशन की पुष्टि भी कर चुका है।

इसके परिशिष्ट

- **परिशिष्ट I:** यह उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है, जिनके विलुप्त होने की संभावना है। इन प्रजातियों के व्यापार को केवल असाधारण परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है।
- **परिशिष्ट II:** वे प्रजातियां हैं, जिनके विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन अगर व्यापार प्रतिबंधित नहीं है, तो संख्या में गंभीर गिरावट हो सकती है। प्रजातियों का व्यापार पूर्व अनुमति से हो सकता है।
- **परिशिष्ट III:** इसमें वे प्रजातियां आती हैं, जो कम से कम एक ऐसे देश में संरक्षित हों, जो एक CITES सदस्य देश हो तथा जिसने उस प्रजाति के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने हेतु सहायता मांगी हो।

- **बिग कैट्स (Big Cats) का संरक्षण:** इस बैठक के दौरान जगुआर के संरक्षण के लिए CITES के सभी सदस्य देशों में सहमति बनी।

स्वास्थ्य विज्ञान

- ♦ पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता
- ♦ चिकनगुनिया वायरस के लिए विश्व के प्रथम टीके को मंजूरी
- ♦ संशोधित एंटीफंगल एजेंट के रोगाणुरोधी गुण
- ♦ खसरा और रूबेला वैक्सीन- 'माबेला'
- ♦ चीन में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी में वृद्धि
- ♦ दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए जेनेरिक दवाएं

कार्यक्रम एवं पहल

- ♦ आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- ♦ वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट-2023

रक्षा प्रौद्योगिकी

- ♦ बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय'

अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड विज्ञान

- ♦ संचार उपग्रह, O3b mPOWER 5 और 6 का प्रक्षेपण

बैठक एवं सम्मेलन

- ♦ प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन

नवीन प्रौद्योगिकी

- ♦ थ्रॉटल एयरोस्पेस को बहुउद्देश्यीय ड्रोन हेतु टाइप-प्रमाणन

स्वास्थ्य विज्ञान

पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता

17 नवंबर, 2023 को आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जिनेवा, स्विट्जरलैंड में एक अभूतपूर्व 'प्रोजेक्ट सहयोग समझौते' में प्रवेश किया है, जिसका लक्ष्य भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा को एकीकृत करना और वैश्विक स्वास्थ्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है।

- ❖ इस समझौते को 'पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते' (The Traditional and Complementary Medicine Project Collaboration Agreement) के नाम से जाना जाता है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा के लिए मील का पत्थर:** आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने संभावना व्यक्त की है कि समझौते का पहला चरण (2023-28) पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणालियों के वैश्विक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।
- ❖ **समझौते के उद्देश्य:** समझौता पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणालियों को मानकीकृत करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं को एकीकृत करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने पर केंद्रित है।
- ❖ **पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति की तैयारी:** WHO और आयुष मंत्रालय पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणालियों को भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के साथ जोड़ने के प्रयासों को संरेखित करते हुए, पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2025-34 को सहयोगात्मक रूप से विकसित करेंगे।
- ❖ **प्रशिक्षण और अभ्यास को मजबूत करना:** समझौते का उद्देश्य पूरक चिकित्सा प्रणाली 'सिद्ध' के प्रशिक्षण और अभ्यास को बढ़ावा देना और पारंपरिक और पूरक दवाओं को सूचीबद्ध करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना है।
- ❖ **अंतरराष्ट्रीय हर्बल फार्माकोपिया विकास:** आयुष मंत्रालय द्वारा WHO के सहयोग से दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियों का एक अंतरराष्ट्रीय हर्बल औषधकोश (International Herbal Pharmacopoeia) विकसित किया जाएगा।
- ❖ **साक्ष्य-आधारित दवाओं का एकीकरण:** जैव विविधता और औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रबंधन पर जोर देते हुए साक्ष्य-आधारित पारंपरिक और पूरक दवाओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा।
- ❖ **पिछला सहयोग:** यह WHO के साथ तीसरा 'परियोजना सहयोग समझौता' है। इससे पूर्व वर्ष 2016 तथा 2017 में पिछले अनुबंधों के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्वीकरण और आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

चिकनगुनिया वायरस के लिए विश्व के प्रथम टीके को मंजूरी

हाल ही में, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (U.S. Food and Drug Administration-USFDA) ने चिकनगुनिया वायरस (Chikungunya Virus) के लिए दुनिया के पहले टीके (Vaccine) को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

- ❖ यूरोपीय वैक्सीन निर्माता वलनेवा (Valneva) द्वारा विकसित यह वैक्सीन 'Ixchiq ब्रांड' नाम से उपलब्ध होगी।
- ❖ इसे 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है, जिन्हें चिकनगुनिया के संपर्क में आने का खतरा अधिक है। इसे मांसपेशियों में इंजेक्शन के माध्यम से एकल खुराक के रूप में दिया जाता है।
- ❖ टीके में चिकनगुनिया वायरस का जीवित, किंतु क्षीण (कमजोर) रूप होता है।

प्रारंभिक परीक्षा

सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-4

भारतीय इतिहास एवं राजव्यवस्था

आगामी प्रारंभिक परीक्षा हेतु 50 अति महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षोपयोगी प्रस्तुति

प्रिय पाठक,

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल के जनवरी 2024 अंक में हम सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-4 प्रस्तुत कर रहे हैं। आगामी प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण श्रृंखला की शुरुआत पत्रिका के अक्टूबर 2023 अंक से हुई थी। इस खंड में प्रकाशित सामग्री यूपीएससी सिविल सेवा तथा राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। विगत 10 वर्षों में आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्नों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के उपरांत यह ज्ञात होता है कि प्राय: परीक्षा में प्रश्न (विशेषकर यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में) दोहराए नहीं जाते, बल्कि सामान्य अध्ययन में कई ऐसे विषय (Topics) हैं, जो अपने विशेष महत्व के कारण अक्सर दोहराए जाते हैं तथा इन विषयों के विभिन्न आयामों से प्रश्न पूछे जाते हैं।

तदनुसार हम जनवरी 2024 के इस अंक में प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-4 के अंतर्गत भारतीय इतिहास एवं राजव्यवस्था के 50 अति महत्वपूर्ण विषयों (Topics) को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक प्रारंभिक परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेगा। आशा है कि सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के दौरान यह सामग्री आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसके संबंध में आप अपना अनुभव हमारे साथ cschindi@chronicleindia.in पर साझा कर सकते हैं।

भविष्य के लिए शुभकामनाएं...

भारतीय इतिहास एवं संस्कृति

1. उत्तर वैदिक काल के दौरान धर्म और धार्मिक परंपराएं....60
2. महाजनपद : महत्वपूर्ण साम्राज्य, अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन....61
3. प्राचीन भारत में गणराज्य....62
4. गुप्त साम्राज्य : अर्थव्यवस्था, समाज एवं धर्म....63
5. संगम युग: समाज, प्रशासन और साहित्य....64
6. प्राचीन काल के प्रमुख विद्वान एवं साहित्यिक कृतियां....65
7. प्राचीन भारत में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास....65
8. भारतीय दर्शन : महत्वपूर्ण विचार एवं संप्रदाय....67
9. मध्यकालीन भारत में धार्मिक संप्रदाय/आंदोलन....67
10. मुगल काल में दृश्य कला का विकास....68
11. विजयनगर साम्राज्य : प्रशासन, सामाजिक-आर्थिक स्थितियां एवं सांस्कृतिक योगदान....69
12. मराठा साम्राज्य : आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्था....70
13. द्रविड़ मंदिर वास्तुकला....71
14. भारत की लोक चित्रकला....72
15. भारत की प्रमुख युद्ध कलाएं....73
16. भारत में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल : मुख्य विशेषताएं....74
17. भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय....75
18. किसान एवं जनजातीय आंदोलन....76
19. ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय : प्रमुख घटनाएं....77
20. भारत में महिला आंदोलन....80
21. ब्रिटिश भू-राजस्व प्रणाली....81
22. ब्रिटिश काल में सामाजिक सुधार के लिए उठाए गए कदम....81
23. ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रेस का विकास....82
24. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी....83
25. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन : संगठन और उनके नेता....85

राजव्यवस्था एवं संविधान

26. प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत....87
27. न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण....87
28. एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत....89
29. विधायी शक्ति का वितरण....90
30. न्यायाधीशों का सुनवाई से खुद को अलग करना....92
31. व्यक्तिगत मानवाधिकार....93
32. ई-गवर्नेंस : अनुप्रयोग एवं पहल....94
33. गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा का अधिकार....95
34. भारत में एसडीजी का स्थानीयकरण....97
35. भारत में डिजिटल मीडिया का विनियमन....97
36. संसदीय लोकतंत्र: भारतीय और ब्रिटिश मॉडल के बीच तुलना....98
37. वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र....99
38. निवारक हिरासत व संवैधाानिक सुरक्षा उपाय....100
39. भारत में नि:शुल्क विधिक सहायता....101
40. संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन....102
41. लोक सभा की विशिष्ट शक्तियां....103
42. संसद के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व....103
43. भारत में प्रमुख वित्तीय नियामक निकाय....104
44. भारत में किशोर न्याय प्रणाली....105
45. उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र....106
46. केंद्रीय जांच एजेंसियां एवं इनके कार्य....106
47. निर्वाचन आयोग: शक्तियां और सीमाएं....108
48. स्पीकर बनाम राज्यपाल: शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान....108
49. लोकपाल और लोकायुक्त: शक्तियां, कार्य और सीमाएं....109
50. भारत में नये राज्यों का गठन....110

प्रतियोगिता क्रॉनिकल

राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं तथा सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित

- ☑ न्यूज बुलेट्स
- ☑ चर्चित शब्दावली
- ☑ राज्य परिदृश्य
- ☑ खेल परिदृश्य
- ☑ लघु संचिका
- ☑ पत्रिका सार
- ☑ संसद प्रश्नोत्तरी
- ☑ परीक्षा सार
- ☑ फैक्ट शीट
- ☑ समसामयिक प्रश्न
- ☑ PIB, AIR, PTI वनलाइनर

प्रतियोगिता क्रॉनिकल नामक यह विशेष खंड 'राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं' तथा अन्य समकक्ष 'सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं' को समर्पित है। इस विशेष खंड की शुरुआत दिसंबर 2023 अंक की पत्रिका से की गई थी। यह खंड प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रमों से संबंधित प्रश्नों को ध्यान में रखकर परिकल्पित किया गया है।

इस खंड में राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग व राज्य अधीनस्थ आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा सीडीएस, रेलवे, बैंकिंग आदि अन्य समकक्ष स्नातक स्तरीय परीक्षाओं हेतु समसामयिक घटनाक्रमों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा में पिछले कुछ वर्षों में पूछे जाने वाले करेंट अफेयर्स के प्रश्नों की प्रकृति में व्यापक बदलाव देखा गया है; अब ये प्रश्न समसामयिक घटनाक्रमों की सामान्य अध्ययन पृष्ठभूमि से पूछे जाते हैं। अतः UPSC-CSE हेतु प्रश्नों के अंतरविषयी एवं बहुविषयी प्रकृति के अनुरूप करेंट अफेयर्स के अध्ययन की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए आलेख, इन फोकस, नियमित स्तंभ तथा विशेषांक के रूप में पत्रिका का शुरुआती भाग सिविल सेवा को समर्पित किया गया है।

सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करेंट अफेयर्स के प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से समसामयिक घटनाक्रमों से ही संबंधित होते हैं तथा इन प्रश्नों की प्रकृति तथ्यात्मक होती है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रमों के बिन्दुवार एवं तथ्यात्मक अध्ययन की आवश्यकता है, न कि इसके विश्लेषणपरक अध्ययन की। परीक्षार्थियों की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम यह नवीन खंड लेकर आए हैं।

न्यूज़ बुलेट्स

राष्ट्रीय परिदृश्य

महिला सैनिकों हेतु मातृत्व अवकाश को मंजूरी

- 5 नवंबर, 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला सैनिकों, नौसैनिकों और वायु योद्धाओं को उनके अधिकारियों के समान मातृत्व, शिशु देखभाल और बच्चे को गोद लेने आदि के संबंध में मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
- यह नियम जारी होने के साथ ही सेना में सभी महिलाओं को, चाहे वह अधिकारी हो या किसी अन्य रैंक की, ऐसी छुट्टियां देना समान रूप से लागू होगा।
- अवकाश नियमों के विस्तार से सशस्त्र बलों से संबंधित महिलाओं को विशिष्ट पारिवारिक एवं सामाजिक मुद्दों के समाधान में अत्यधिक सहायता मिलेगी।
- इस कार्य से सेना में महिलाओं की कार्य स्थितियों में सुधार होगा तथा उन्हें पेशेवर एवं पारिवारिक जीवन के क्षेत्रों में बेहतर तरीके से संतुलन बनाने में सहायता मिलेगी।

इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो

- 2 नवंबर, 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु, कर्नाटक में तीन दिवसीय 'इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो' का उद्घाटन किया।
- यह शो लघु उद्योग भारती एवं आईएमएस (IMS) फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया तथा इसे रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा समर्थित किया गया।
- भारत में एमएसएमई क्षेत्र 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र अत्यधिक गतिशील है, जो भारत के विनिर्माण उत्पादन में लगभग 35% का योगदान देता है।

सर्वोच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीश नियुक्त

- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर, 2023 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के 3 मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई।
- ये 3 न्यायाधीश हैं- जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता।
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 नवंबर, 2023 को इन तीनों जजों के नाम की सिफारिश की थी।
- 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम स्वीकृत क्षमता (34) तक पहुंच गई है।

भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर

- 3 नवंबर, 2023 को केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई से भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर, कोस्टा सेरेना जहाज की पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई।
- सरकार की परिकल्पना भारत को मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत, एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख क्रूज केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में मंत्रालय ने 2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज यात्रियों को ले जाने का लक्ष्य रखा था।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु पहली क्षेत्रीय क्षमता-निर्माण कार्यशाला

- 3 से 4 नवंबर, 2023 तक दीमापुर, नागालैंड में भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए पहली क्षेत्रीय क्षमता-निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- इस कार्यशाला की परिकल्पना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है।
- इसके माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, पहचान, दस्तावेजीकरण एवं सूचीकरण के लिए कई हितधारकों और संरक्षकों की क्षमता को मजबूत करना है।

बाल विज्ञान महोत्सव

- 6 नवंबर, 2023 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू में सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (CSIR-IIIM) द्वारा आयोजित 'बाल विज्ञान महोत्सव' (Children Science Festival) का उद्घाटन किया।
- इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीएसआईआर जिज्ञासा कार्यक्रम (CSIR Jigyasa programme) के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की गई है, जिसने देश भर के वैज्ञानिकों के साथ छात्रों और वैज्ञानिकों के बीच एक मजबूत जुड़ाव बनाया है।
- जिज्ञासा, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के सहयोग से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा कार्यान्वित एक छात्र-वैज्ञानिक कनेक्ट कार्यक्रम है।

चर्चित शब्दावली

रैटहोल खनन

हाल ही में, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त सिल्कयारा सुरंग से 41 श्रमिकों को बाहर निकालने हेतु संचालित किये गए बचाव अभियान में रैटहोल खनन (Rat-Hole Mining) तकनीक का प्रयोग किया गया।

- यह पारंपरिक रूप से प्रचलित कोयला निष्कर्षण की एक विधि है। खनन की इस विधि में श्रमिकों के प्रवेश तथा कोयला निकालने के लिए आमतौर पर तीन-चार फुट गहरी संकीर्ण गड्ढों की खुदाई की जाती है।
- यह संकीर्ण गड्ढ़ा आमतौर पर एक व्यक्ति के प्रवेश कर कोयला निष्कर्षण के लिए पर्याप्त होता है।

जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी

यह जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक तकनीक प्रक्रिया है जो किसी विशिष्ट जीन को एक प्रजाति की सम्पूर्ण आबादी में प्रसारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

- जीन ड्राइव के माध्यम से एक आनुवंशिक लक्षण की त्वरित और व्यापक तरीके से प्रसार किया जा सकता है।
- जीन ड्राइव किसी जीव की विशिष्ट आबादी को आनुवंशिक रूप से संशोधित करने का एक प्रभावी साधन प्रदान करती है।

एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट

यह नासा का एक अंतरीक्ष में स्थापित किया जाने वाला उपकरण है जो वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों (Atmospheric Gravity Waves - AGWs) को समझने में सहायक होगा।

- इसका निर्माण उटाह स्टेट यूनिवर्सिटी स्पेस डायनेमिक्स लेबोरेटरी द्वारा किया गया है।
- नासा के आगामी मिशन के माध्यम से इसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station - ISS) के बाहरी हिस्से पर स्थापित किया जाना है।

सॉवरेन ग्रीन बांड

सॉवरेन ग्रीन बांड किसी सरकार द्वारा लिया जाने वाला एक प्रकार का ऋण है जो पर्यावरण या जलवायु के लिए प्रासंगिक पहल के लिए धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है।

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा ग्रीन बॉन्ड को सरकार ने पांच साल की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किया है तथा इसके लिए 7.25 प्रतिशत रिटर्न निर्धारित की गई है।
- 2023 की दूसरी छमाही में ₹16,000 करोड़ जुटाए गए थे। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही में ₹20,000 करोड़ जुटाना है।

व्हाइट होल

हाल ही में, एक इतालवी भौतिक विज्ञानी कार्लो रोवेली ने व्हाइट होल की दिलचस्प अवधारणा पर प्रकाश डाला हैं।

- एक सिद्धांत के रूप में, व्हाइट होल (White hole) एक काल्पनिक क्षेत्र है जिसमें बाहर से प्रवेश संभव नहीं है, हालाँकि इससे प्रकाश और पदार्थ का बहिर्गमन संभव है।
- कार्लो रोवेली के अनुसार, व्हाइट होल से संबन्धित अवधारणा को गणितीय सिद्धांतों के आधार पर सिद्ध करके भी दिखाया जा सकता है।

पर्यावरण डी. एन. ए

हाल ही में, 'लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला' (Laboratory for the Conservation of Endangered Species - LaCONES) के शोधकर्ताओं ने जैव विविधता मूल्यांकन से संबंधित एक अभूतपूर्व विधि विकसित की है।

- इनके द्वारा फ्री-फ्लोटिंग पर्यावरणीय डीएनए (Environmental DNA - eDNA) के माध्यम से जैव विविधता मूल्यांकन को संभव बनाया गया है, जो इस उद्देश्य के लिए व्यापक भौतिक नमूना संग्रह की आवश्यकता समाप्त करता है।
- विकसित की गई नई विधि सस्ती, तेज और बड़े पारिस्थितिक तंत्रों के लिए 'स्केलेबल' है। यह मीठे पानी और समुद्री दोनों वातावरणों में जैव विविधता की निगरानी एवं संरक्षण को सक्षम बनाता है।

सफेद हाइड्रोजन

पूर्वोत्तर फ्रांस में जीवाश्म ईंधन की खोज कर रहे वैज्ञानिकों को सफेद हाइड्रोजन (White Hydrogen) का एक बड़ा भंडार मिला है जो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन माना जाता है।

- जमीन से 1,250 मीटर नीचे स्थित इस भंडार में हाइड्रोजन की मात्रा 20% अधिक है। अनुमान है कि इसमें 6 मिलियन से 250 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन है, जो विश्व के सबसे बड़े ज्ञात भंडारों में से एक माना जा रहा है।
- सफेद हाइड्रोजन, जलने पर केवल पानी उत्पन्न करता है तथा किसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन नहीं करता हैं।

फ्रैक्टल

भौतिक विज्ञानी क्वांटम प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए फ्रैक्टल ज्यामिति दृष्टिकोण (Fractal Geometry Approach) का उपयोग कर रहे हैं।

- फ्रैक्टल, असीम रूप से कभी न खत्म होने वाला एक जटिल पैटर्न हैं जो विभिन्न पैमानों पर स्व-समान (Self-Similar) होते हैं।
- फ्रैक्टल का प्रत्येक भाग, चाहे आपने कितना भी जूम इन या जूम आउट किया गया हो, पूरी छवि के समान दिखता है।

राज्य परिदृश्य

उत्तर प्रदेश

हलाल प्रमाणन वाले उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

18 नवंबर, 2023 को, उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 'हलाल-प्रमाणित' उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया।

- यह प्रतिबंध खाद्य उत्पादों के साथ-साथ दवाओं पर भी लागू होगा। हालांकि, विदेश भेजे जाने वाले उत्पादों पर छूट रहेगी।
- अगर राज्य में काम करने वाला कोई भी निर्यातक अपने खाद्य उत्पाद या दवाइयां उन देशों के लिए तैयार करता है, जहां केवल हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य उत्पाद स्वीकार किए जाते हैं, तो उसे छूट दी जाएगी।
- हलाल सर्टिफिकेट की शुरुआत वर्ष 1974 से हुई थी। हलाल सर्टिफिकेट पहले सिर्फ मांस से जुड़े हुए उत्पादों के लिए दिया जाता था। 1993 में हलाल सर्टिफिकेट अन्य प्रोडक्ट जैसे कॉस्मेटिक, साबुन, तेल आदि के लिए भी देना शुरू कर दिया गया।

17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर

9 नवंबर, 2023 को राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण, डिजिटलीकरण, मैपिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) को अधिक सुविधाजनक बनाने जैसी 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है।

- सॉफ्टवेयर विकास की जिम्मेदारी श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को सौंपी गई है। श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है, जो राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती है और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन रखती है।
- विज्ञप्ति में कहा गया है कि एसआईएल विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और आधार प्रमाणीकरण सेवाओं सहित अन्य कार्यों के लिए राज्य नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करती है।

सीएनजी मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट

26 नवंबर, 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी के रविदास घाट पर शहर के दूसरे फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट (MRU) स्टेशन का उद्घाटन किया।

- नया सीएनजी स्टेशन रणनीतिक रूप से नाविकों को सुविधा प्रदान करता है तथा ईंधन भरने के लिए नमो घाट की यात्रा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- सीएनजी को ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल की जगह उपयोग करने से धन की बचत होती है।
- फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का निर्णय स्वच्छ ऊर्जा की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

सेफ सिटी प्रोजेक्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित शहर परियोजना (Safe City Project) शुरू की है।

- सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए सरकार 17 नगर निगमों के प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ-साथ गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करेगी।
- इस परियोजना के तहत उपद्रवियों के जमावड़े और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए इन शहरों में निजी कोचिंग संस्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
- सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती चरण में सरकार द्वारा राज्य के 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर के 2500 स्कूलों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए चिह्नित किया गया था।

अनपरा-ई तापीय परियोजना

उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL) ने 20 नवंबर, 2023 को 'अनपरा-ई' तापीय परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

- सोनभद्र जिले के अनपरा में स्थापित होने वाली इस परियोजना के तहत 1,600 मेगावॉट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
- इन इकाइयों के निर्माण पर लगभग 18,624 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
- यह परियोजना, मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी, जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL) और एनटीपीसी का संयुक्त उद्यम है।

बिहार

बिहार में आरक्षण की सीमा में वृद्धि

17 नवंबर, 2023 को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा 'बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक' को मंजूरी दे दी गई।

- यह विधेयक बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया था।
- बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (BC) और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए आरक्षण की सीमा पूर्व के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत की गई है।

खेल परिदृश्य

चर्चित खेल व्यक्तित्व

विराट कोहली

विराट कोहली ने 15 नवंबर, 2023 को सचिन तेंदुलकर के एकदिवसीय 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपना 50वां एकदिवसीय शतक बनाकर इतिहास रचा।

- कोहली ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 50वां एकदिवसीय शतक बनाया।
- इसके साथ ही विराट किसी एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं।
- कोहली ने 106 गेंदों पर अपना 50वां एकदिवसीय शतक बनाया।
- कोहली ने इससे पहले कोलकाता के इडेन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक बनाते हुए सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की बराबरी की थी। विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 80 शतक बना चुके हैं। उन्होंने वनडे में 50, टेस्ट में 29 और टी-20 में 1 शतक बनाया है।

संजीव मलिक

आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है।

- 42वां संस्करण 4 से 11 नवंबर, 2023 तक कार्टाजेना, कोलंबिया में आयोजित किया गया था।
- कर्नल संजीव मलिक, वर्तमान में राष्ट्रपति के अंग रक्षक के रूप में राष्ट्रपति भवन में तैनात हैं।
- मलिक ने 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर और क्रॉस-कंट्री स्पर्द्धाओं में जीत हासिल की। वर्ष 2023 में यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले संजीव मलिक एकमात्र एथलीट हैं।
- मलिक, वर्ष 1978 में शुरू हुए विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों के कुछ चुनिंदा एथलीटों में शामिल हो गए हैं।
- 1978 के बाद से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल, स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ओलंपिक खेल माना जाता है।

नोवाक जोकोविच

सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इटली के ट्यूरिन में 19 नवंबर, 2023 को इटालवी खिलाड़ी जानिक सिनर को हराकर अपना रिकॉर्ड 7वां एकल एटीपी फाइनल खिताब जीता।

- इस जीत के साथ जोकोविच ने स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी रोजर फेडरर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिन्होंने 6 एटीपी फाइनल खिताब जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने 5 नवंबर, 2023 को बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोविक को 6-4, 6-3 से हराकर अपना 7वां पेरिस मास्टर्स खिताब भी जीता।
- जोकोविच का यह 40वां 'एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब' (ATP Masters 1000 crown) और उनके करियर का 97वां खिताब था।
- जोकोविच ने वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और US ओपन खिताब जीते हैं। जोकोविच को 2023 के विंबलडन फाइनल में कार्लोस अल्कराज से हार का सामना करना पड़ा था।

सचिन तेंदुलकर

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 1 नवंबर, 2023 को क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया।

- यह प्रतिमा सचिन के जीवन के 50 वर्षों को समर्पित है। इस प्रतिमा को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चित्रकार-मूर्तिकार प्रमोद कांबले ने बनाया है। सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था।
- सचिन को इस प्रतिमा में उनके ट्रेडमार्क 'लॉफ्टेड ड्राइव' पोज में चित्रित किया गया है।

बहु-खेल स्पर्द्धा

37वां राष्ट्रीय खेल

26 अक्टूबर-9 नवंबर, 2023 तक गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 80 स्वर्ण सहित 228 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा।

- सर्विसेस 66 स्वर्ण सहित 126 पदकों के साथ दूसरे और हरियाणा 62 स्वर्ण सहित 192 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- महाराष्ट्र ने नेशनल गेम्स 2023 मेडल टैली में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती, जो नेशनल गेम्स में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाती है।
- ओलंपिक तैराक श्रीहरि नटराज (8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य) को 37वें नेशनल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया।
- जिमनास्ट संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक (4 स्वर्ण और 1 रजत) को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया।

लघु संचिका

नियुक्ति

गिरीश चंद्र मुर्मू

हाल ही में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 के लिए **संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल** (UN Panel of External Auditors) का **उपाध्यक्ष** चुना गया है।

- उनका उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव **बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल के 63वें सत्र** के दौरान किया गया, जिसे 20-21 नवंबर, 2023 के दौरान **न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय** में आयोजित किया गया। बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल में विश्व के 12 सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों (Supreme Audit Institutions - SAIs) के प्रमुख शामिल होते हैं।
- बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल द्वारा **संयुक्त राष्ट्र** सचिवालय, उसके कार्यक्रमों और विशेष एजेंसियों का **ऑडिट** किया जाता है।
- वर्तमान में इस पैनल में कनाडा, चिली, फ्रांस, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, फिलीपींस, रूस, स्विटजरलैंड और ब्रिटेन के प्रतिनिधि शामिल हैं।

सौरव गांगुली

21 नवंबर, 2023 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को **पश्चिम बंगाल का ब्रांड एंबेसडर** नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के संबंध में घोषणा **कोलकाता में** आयोजित द बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 के दौरान की गई।

- **इससे पूर्व** पश्चिम बंगाल के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता **शाहरुख खान** थे।
- ध्यान रहे है कि सौरव गांगुली को त्रिपुरा सरकार ने भी **त्रिपुरा पर्यटन** का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।

हीरालाल सामरिया : मुख्य सूचना आयुक्त

6 नवंबर, 2023 को सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को **केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) के प्रमुख** के रूप में नियुक्त किया गया।

- भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई।
- हीरालाल सामरिया को यशवर्धन कुमार सिन्हा के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो अक्टूबर 2023 में रिटायर हुए थे। श्री समारिया देश के इस सर्वोच्च पर नियुक्त होने वाले दलित समुदाय के प्रथम व्यक्ति हैं।
- **केंद्रीय सूचना आयोग:** आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) करता है और इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुसार, वर्तमान में **8 सूचना आयुक्तों के पद खाली** हैं तथा केवल दो सूचना आयुक्त हैं।

सुरेंद्र कुमार अधाना

हाल ही में, सुरेंद्र कुमार अधाना को **संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति** (Advisory Committee on Administrative - Budgetary Questions - ACABQ) के लिए पुन: चुन लिया गया है। उनका निर्वाचन 2024-26 की अवधि के लिए किया गया है।

- प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति में महासभा द्वारा चुने गए **21 सदस्य** शामिल हैं।
- इस समिति को **3 वर्ष के कार्यकाल** के लिए चुना जाता है और व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इसे सावधानीपूर्वक संरचित किया जाता है।
- सलाहकार समिति के प्रमुख कार्यों में महासचिव द्वारा **महासभा में प्रस्तुत बजट की जांच करना** और उस पर रिपोर्ट देना, महासभा को संदर्भित किसी भी प्रशासनिक और **बजटीय मामले पर सलाह देना**, महासभा की ओर से विशेष एजेंसियों के प्रशासनिक बजट और ऐसी एजेंसियों के साथ वित्तीय व्यवस्था के प्रस्तावों की जांच करना आदि शामिल है।

राजेंद्र मेनन

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन को 4 वर्ष के लिए **सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष** के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।

- न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक यानी 6 जून, 2027 तक पद पर रहेंगे।
- सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) एक सैन्य न्यायाधिकरण (Military Tribunal) है, जिसके पास नियुक्तियों, नामांकन और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों के न्यायनिर्णयन या परीक्षण की शक्ति है। इसकी स्थापना **सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत अगस्त 2009** में की गई थी।
- यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2008 के अनुसार अपनी कार्यवाही का संचालन करता है।
- इसकी **प्रधान पीठ नई दिल्ली में** स्थित है।

साइमा वाजेद

1 नवंबर, 2023 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक चुना गया।

- साइमा वाजेद एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। उन्हें दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय समिति के **76वें सत्र के दौरान** इस भूमिका के लिए चुना गया है।

पत्रिका सार

प्रायः ऐसा देखा गया है कि UPSC एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं सहित अन्य समकक्ष एवं सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में योजना, कुरुक्षेत्र एवं विज्ञान प्रगति जैसी प्रमुख पत्रिकाओं से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम प्रतियोगी छात्रों के लिए इन पत्रिकाओं के परीक्षोपयोगी बिन्दुओं का प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं।

योजना (नवंबर 2023)

जी20: पृथ्वी, लोग, शांति और समृद्धि के लिए

भारत की अध्यक्षता में जी20 सम्मेलन के दौरान वैश्विक सहमति से की गई- 'नई दिल्ली लीडर्स घोषणा' (NDLD) सामान्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने में एकता की शक्ति को रेखांकित करती है।

- **'नई दिल्ली लीडर्स घोषणा'** की **मुख्य बातों में**- मजबूत, स्थाई, संतुलित एवं समावेशी विकास; एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाना; दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता; 21वीं शताब्दी के लिए बहुपक्षीय संस्थान तथा प्रौद्योगिकी परिवर्तन एवं डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को शामिल किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र की **नवीनतम सतत विकास लक्ष्य (SDG) रिपोर्ट** के अनुसार केवल 12% SDG लक्ष्य ही सही ट्रैक पर हैं। इसके अनुसार 30% लक्ष्य वर्ष 2015 के बाद से स्थिर हो गए हैं अथवा पीछे चले गए हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार **वर्ष 2015 से 2020 तक 50 मिलियन हेक्टेयर वनों की हानि** और बढ़ती मौसम संबंधी आपदाओं के कारण **1.5 डिग्री तापमान में वृद्धि** हुई है।
- **'SDG पर प्रगति में तेजी लाने के लिए जी20-2023 कार्य योजना'** एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो वित्त और प्रौद्योगिकी तक पहुंच स्थापित करने के साथ न्यायसंगत, मजबूत, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।
- सम्मेलन में **'सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता'** अपनाया गया, इसके तहत सदस्य देशों ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के प्रयासों को बढ़ावा देने पर सहमति प्रकट की है।
- जी20 पर नई दिल्ली घोषणा पत्र में **'वन फ्यूचर एलाइंस'** नामक स्वैच्छिक पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। यह पहल निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन में सहायता करेगी।
- घोषणा पत्र वर्ष 2024 में जलवायु वित्त के लिए **'नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य' (NCQG)** निर्धारित करने का समर्थन करता है। यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी, पता लगाने योग्य तथा पारदर्शी होना चाहिए।
- इस घोषणा पत्र में विकासशील देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) को लागू करने के लिए **वर्ष 2030 से पहले लगभग 5.8-5.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण की आवश्यकता** का उल्लेख किया गया है।
- घोषणा पत्र के अनुसार **महिला सशक्तिकरण पर एक अलग कार्य समूह** का गठन किया जाएगा। यह समूह लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व को प्राथमिकता देने का काम करेगा।
- भारत की जी20 अध्यक्षता में **'वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट'** का आयोजन वर्ष के आरंभ में किया गया था, इसमें 125 देश तथा 18 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे।
- ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के क्रम में भारत के प्रस्ताव पर **'अफ्रीकी संघ' (AU)** को जी20 के स्थाई **सदस्य के रूप में शामिल** किया गया है।
- भारत ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरीशस, और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर **'ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस' (GBA)** की शुरुआत की है।
- GBA जैव ईंधन पर **ज्ञान के केंद्रीय भंडार** और एक **विशेषज्ञ केंद्र** के रूप में कार्य करेगा।
- सम्मेलन में **'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे' (IMEC)** की स्थापना के लिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- IMEC परियोजना **'वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी' (PGII)** का हिस्सा है। **PGII की घोषणा वर्ष 2021** में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित **G-7 शिखर सम्मेलन** में की गई थी। **'ट्रांस-अफ्रीका कॉरिडोर'** PGII के तहत एक अन्य परियोजना है।

भाषिणी ऐपः भाषा विविधता जनित डिजिटल अंतराल को पाटने वाला सेतु

भाषिणी ऐप और उसकी जुगलबंदी बॉट को **'इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय'** की पहल पर विकसित किया गया है।

- यह ऐप **'एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन'** के अनुसार केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विभिन्न भाषा-भाषी लोगों को एक साथ लाकर भारत के सदियों पुराने **'वसुधैव कुटुम्बकम'** के सिद्धांत के तहत जोड़ता है।

संसद प्रश्नोत्तरी

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य: वनलाइनर रूप में

जूट उद्योग

- भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन (IJMA) के अनुसार, भारत में लगभग कितनी जूट मिलें हैं? - **93 जूट मिल**
- भारत में पहली जूट मिल 1854 में कहाँ पर स्थापित की गई थी? - **रिशिरा (कलकत्ता)**
- जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों ने खाद्यान्न के 100% उत्पादन एवं चीनी उत्पादन का कितना प्रतिशत जूट बैग में पैक करना अनिवार्य कर दिया गया है? - **20% जूट बैग**
- विश्व में जूट (कच्चा जूट और जूट का सामान, जो वैश्विक उत्पादन में क्रमशः 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है) का सबसे बड़ा उत्पादक देश है - **भारत**

सीखो और कमाओ (SAK) योजना

- सीखो और कमाओ (SAK) योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? - **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**
- सीखो और कमाओ (SAK) योजना का प्रमुख उद्देश्य है - **अल्पसंख्यक युवाओं (14-45 वर्ष) के कौशल को उनकी क्षमताओं, वर्तमान आर्थिक रुझानों और विपणन योग्यता के आधार पर उन्हें विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में उन्नत करना।**
- 'सीखो और कमाओ' योजना ने कुल प्रशिक्षित लाभार्थियों में से कितना प्रतिशत महिला लाभार्थियों के लिए निर्धारित करने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है? - **33%**

समुद्रयान परियोजना

- गहरे समुद्र की खोज के लिए भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है? - **समुद्रयान परियोजना**
- इस बहु-संस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय है? - **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**
- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई द्वारा विकसित मत्स्य 6000 क्या है? - **एक मानव चालित पनडुब्बी**

निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन (LTTD)

- ऐसी प्रक्रिया जो खारे पानी से खनिज घटकों को निकाल लेती है उसे कहा जाता है। - **अलवणीकरण**
- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) की स्थापना 1993 में भारत में किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी? - **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**
- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई ने कावारत्ती, मिनिकॉय और अगत्ती की स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहां पर दुनिया का पहला निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन (LTTD) संयंत्र विकसित किया है। - **लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती में**
- एलटीटीडी किस प्रक्रिया के तहत गर्म सतह वाले समुद्री जल को कम दबाव पर अचानक वाष्पित किया जाता है और वाष्प को ठंडे गहरे समुद्री जल के साथ संघनित किया जाता है? - **एलटीटीडी**

मीथेन उत्सर्जन

- भारत की तृतीय द्विवार्षिक मीथेन उत्सर्जन अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016 में भारत का मीथेन उत्सर्जन कितना मिलियन टन था? - **409 मिलियन टन CO_2 समकक्ष**
- मीथेन उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र से 73.96 प्रतिशत, अपशिष्ट क्षेत्र से 14.46 प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्र से 10.62 प्रतिशत, जबकि औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं उत्पाद उपयोग क्षेत्र से उत्सर्जन का प्रतिशत था। - **लगभग 0.96 प्रतिशत**
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किस मिशन के तहत चावल की खेती में मीथेन उपशमन कार्य सहित जलवायु अनुकूलन पद्धतियां शामिल हैं? - **राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (NMSA)**
- राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन कृषि नवाचार परियोजना (NICRA) के तहत किस संगठन ने चावल से मीथेन की उपशमन क्षमता वाली कई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं? - **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)**
- किन पहलों के माध्यम से गांवों में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के अलावा, मवेशियों के अपशिष्ट उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है? - **गोबर (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज) धन योजना और जैविक खाद कार्यक्रम**

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को कब अधिसूचित किया गया है? - **12 अगस्त, 2021 को**
- इस अधिसूचना के तहत कितने माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी 31 दिसंबर, 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है? - **120 माइक्रोन**
- प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को निर्माता, आयातक और ब्रांड मालिकों द्वारा किस व्यवस्था के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से एकत्र और प्रबंधित किया जाएगा? - **विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR)**
- राज्य प्रदूषण निकायों के साथ कौन-सा संस्थान मिलकर प्रतिबंध की निगरानी करेगा, उल्लंघनों की पहचान करेगा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पहले से निर्धारित जुर्माना लगाएगा? - **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

परीक्षा सार

ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) द्वारा 15 अक्टूबर, 2023 को आयोजित ओडिशा सिविल सेवा (OCS) प्रारंभिक परीक्षा 2023 तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 3 सितंबर, 2023 को आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) परीक्षा 2023 पर आधारित

ओडिशा सिविल सेवा (OCS) प्रारंभिक परीक्षा 2023

राजव्यवस्था

- **निर्वाचन आयोग:** भारतीय संविधान के भाग-15 में अनुच्छेद 324-329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है।
  - यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
  - निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी।
  - प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे।
  - अनुच्छेद-329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्णन का प्रावधान है।
- **न्याय पंचायत:** इसके गठन की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी।
  - अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था, जिसने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था के गठन का सुझाव दिया था।
  - न्याय पंचायत एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होती है, जिसका कार्य स्थानीय विवादों का समाधान करना था।
- **महान्यायवादी:** अनुच्छेद-76 के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
  - महान्यायवादी की नियुक्ति सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  - यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
  - यह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है।
  - इसका संविधान द्वारा निश्चित कार्यकाल नहीं होता है।
- **संसद में विधेयक:** सरकारी विधेयक सदन में पास न होने की स्थिति में सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है।
  - सरकारी विधेयक सदन में पेश करने के लिए 7 दिन का पूर्व नोटिस देना पड़ता है।
  - कराधान (संशोधन) विधेयक-2021 धन विधेयक की श्रेणी में आता है।
  - केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2021 साधारण विधेयक की श्रेणी में आता है।
- **बहुमत के प्रकार: पूर्ण बहुमत** - सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक।
  - **साधारण बहुमत:** सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50% से अधिक।
  - **प्रभावी बहुमत:** सदन की प्रभावी क्षमता का बहुमत।
  - **प्रभावी क्षमता:** रिक्त स्थानों को छोड़कर सदन की संपूर्ण संख्या।
  - **विशेष बहुमत:** सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों को 2/3 संख्या।
- **संसद की बैठकें:** 1955 में लोकसभा की समिति ने वर्ष में 3 सत्र आयोजित करने का सुझाव दिया।
  - बजट सत्र फरवरी से मई के मध्य।
  - मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के मध्य।
  - शीतकालीन सत्र नवम्बर से दिसंबर के मध्य।
- **विधि के समक्ष समता:** यह एक ब्रिटिश विचार है, जिसमें कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान होंगे तथा किसी को कोई कानूनी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा।
  - **विधियों का समान संरक्षण:** यह अमेरिकी विचार है, जिसमें समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
  - **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया:** सरकार या कानूनों का संचालन विधि या संविधान के अनुसार भारत में यह विचार जापान से ग्रहण किया गया है।
- **दबाव समूह:** जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। जैसे- हरिजन सेवक संघ, मजदूर संघ, भारतीय किसान यूनियन आदि।
  - इनका लोक नीति के निर्माण में काफी प्रभाव होता है।
- **सार्वजनिक नीति चक्र:** वैल्यू सेटिंग-नीति हेतु मूल्यों का निर्धारण/समेकन।
  - नीति निर्माण: नीति प्रक्रियाओं की खोज एवं नीति निर्माण।
  - नीति कार्यान्वयन: नीति को जमीनी स्तर पर लागू करना।
  - नीति प्रतिक्रिया: जनता से नीति के प्रतिफल के बारे में राय लेना।
  - एजेंडा सेटिंग: नीति को विकल्प के रूप में व्यवस्थापित करना।
  - पॉलिसी एडॉप्शन
- **सुशासन:** विकास के लिए किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीकों के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के 8 सिद्धान्त दिये हैं- सहभागिता, सर्वसम्मति उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल, न्यायसंगत एवं समावेशी, विधि के शासन का पालन।
- **लोकनीति का आशय:** यह नियमों एवं विनियमों के अनुसार कार्यों को करने का तरीका है।

फैक्ट शीट

बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023

26 नवंबर, 2023 को गुवाहाटी में 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कार्यक्रम' के अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने 'बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी-2023' (Basic Animal Husbandry Statistics 2023) जारी की। इस सांख्यिकी में वर्ष 2022-23 के लिए दूध, अंडे, मांस और ऊन के उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है।

- यह रिपोर्ट मार्च 2022 से फरवरी 2023 के बीच आयोजित पशु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (Animal Integrated Sample Survey) पर आधारित है।

दुग्ध उत्पादन

- **कुल दुग्ध उत्पादन:** 2022-23 के दौरान देश में कुल दूध उत्पादन 230.58 मिलियन टन होने का अनुमान है, 2018-19 में 187.75 मिलियन टन थी। पिछले 5 वर्षों में इसमें 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य:** कुल दूध उत्पादन में 15.72% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, इसके बाद राजस्थान (14.44%), मध्य प्रदेश (8.73%), गुजरात (7.49%) और आंध्र प्रदेश (6.70%) का स्थान हैं।

अंडा उत्पादन

- **कुल अंडा उत्पादन:** 2022-23 के दौरान देश में कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन अनुमानित है, जो 2018-19 के दौरान 103.80 बिलियन था। पिछले 5 वर्षों में देश में अंडा उत्पादन 33.31% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य:** कुल अंडा उत्पादन में 20.13% हिस्सेदारी के साथ आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, इसके बाद तमिलनाडु (15.58%), तेलंगाना (12.77%), पश्चिम बंगाल (9.94%) और कर्नाटक (6.51%) का स्थान है।

मांस उत्पादन

- **कुल मांस उत्पादन:** 2022-23 के दौरान देश में कुल मांस उत्पादन 9.77 मिलियन टन होने का अनुमान है, ध्यात्वय है कि 2018-19 देश में कुल मांस उत्पादन 8.11 मिलियन टन था। पिछले 5 वर्षों में देश में कुल मांस उत्पादन में 20.39% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **शीर्ष मांस उत्पादक राज्य:** उत्तर प्रदेश 12.20% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद पश्चिम बंगाल (11.93%), महाराष्ट्र (11.50%), आंध्र प्रदेश (11.20%) और तेलंगाना (11.06%) का स्थान हैं।

ऊन उत्पादन

- **कुल ऊन उत्पादन:** 2022-23 के दौरान देश में कुल ऊन उत्पादन 33.61 मिलियन किलोग्राम होने का अनुमान है। ध्यात्वय है कि 2018-19 के दौरान 40.42 मिलियन किलोग्राम था। पिछले 5 वर्षों में इसमें 16.84% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।
- **शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य:** राजस्थान 47.98% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद जम्मू और कश्मीर (22.55%), गुजरात (6.01%), महाराष्ट्र (4.73%) और हिमाचल प्रदेश (4.27%) का स्थान हैं।

भारत का पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र (Tourism and Hospitality Sector) में निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए, भारत स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति देता है। पिछले 8 वर्षों में, 2014 से 2022 तक, भारत में होटल और पर्यटन क्षेत्र में 9.2 बिलियन डॉलर की एफडीआई राशि का महत्वपूर्ण प्रवाह देखा गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **विदेशी पर्यटक आगमन:** 2021 की समान अवधि के दौरान 1.52 मिलियन की तुलना में भारत को 2022 के दौरान 6.19 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) प्राप्त हुए।
- **विश्व आर्थिक मंच विकास सूचकांक:** भारत विश्व आर्थिक मंच यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक (2022) में 54वां स्थान रखता है।
- **भारत सरकार का विजन:** समावेशी विकास के माध्यम से 2030 तक पर्यटन में लगभग 140 मिलियन नौकरियां पैदा करना, क्रूज पर्यटन, इकोटूरिज्म और साहसिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।
- **2028 तक अनुमानित राजस्व:** भारत के पर्यटन और आतिथ्य उद्योग से 2028 तक +59 बिलियन से अधिक का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- **विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) अनुमान:** इसको 2028 तक 30.5 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- आरसीएस उड़ान-3 (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान-3) पर्यटन कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2022 तक कुल 31 पर्यटन मार्गों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा चुका है।
- पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत की G20 प्रेसीडेंसी और India@75 के तहत पर्यटन मंत्रालय ने वर्तमान वर्ष को 'विजिट इंडिया ईयर 2023' के रूप में नामित किया है।
- भारत ने 2022 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया। अर्नतिम आंकड़ों से पता चलता है कि देश को विदेशी मुद्रा आय में 1,34,543 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो 2021 में दर्ज 65,070 करोड़ रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि है। ■

समसामयिक प्रश्न

नवंबर 2023 के घटनाक्रम पर आधारित

1. हाल ही में खबरों में रहा शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?

(a) कर्नाटक (b) महाराष्ट्र
(c) मध्य प्रदेश (d) आंध्र प्रदेश

2. संपीड़ित बायो-गैस सम्मिश्रण दायित्व (CBO) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. सीबीओ वित्त वर्ष 2024-2025 तक स्वैच्छिक रहेगा एवं अनिवार्य सम्मिश्रण दायित्व वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होगा।
2. इसकी निगरानी तथा कार्यान्वयन केंद्रीय रिपोजिटरी बॉडी (CRB), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
3. वित्त वर्ष 2025-26, 2026-27 तथा 2027-28 के लिए सीबीओ को कुल सीएनजी अथवा पीएनजी खपत का क्रमशः 1%, 3% और 4% रखा जाएगा, जबकि वर्ष 2028-29 से सीबीओ 5% होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) उपरोक्त में से कोई नही

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. लोकटक झील कई पौधों की प्रजातियों के साथ फुमडी नामक अद्वितीय तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है।
2. यह मणिपुर राज्य में खारे पानी का झील है, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है।
3. आईयूसीएन (IUCN) की लाल सूची (Red List) में लुप्तप्राय (Endangered) के रूप में सूचीबद्ध संगाई हिरण केवल लोकटक झील के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं।

सही कथन चुनें:

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

4. निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार करें-

1. सोशल इम्पैक्ट फंड (SIF) वैश्विक दक्षिण (Global South) में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन को तेजी से ट्रैक करने के लिए सरकार के नेतृत्व वाली बहुहितधारक पहल है।
2. यह फंड डीपीआई सिस्टम (DPI systems) विकसित करने में देशों को अपस्ट्रीम तकनीकी तथा गैर-तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
3. भारत ने 32 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक प्रतिबद्धता का वादा किया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म (IRRAP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इसका उद्देश्य शेयर बाजार में कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण निवेशकों को होने वाले जोखिम को कम करना है।
2. यह प्लेटफॉर्म भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा विकसित किया गया है।
3. यह निवेशकों को आईआरआरए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी खुली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने एवं लंबित ऑर्डर को रद्द करने का अवसर प्रदान करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

6. हाल ही में समाचारों में देखा गया ओनाटुकारा तिल, भौगोलिक संकेत (GI) उत्पाद निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाया जाता है?

(a) केरल (b) तमिलनाडु
(c) आंध्र प्रदेश (d) कर्नाटक

7. ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स (GLV) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. वे पौधों में मौजूद यौगिकों का समूह हैं जो हवा में छोड़े जाने पर सुखद गंध पैदा करते हैं।
2. जीएलवी आंतरिक पौध-रक्षा प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करते हैं और फसलों के कीट क्षति को कम करने में मदद कर सकते हैं।

सही कथन चुनें:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

8. हाल ही में समाचारों में आए RISE एक्सेलेरेटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह भारत और अमेरिका की एक संयुक्त पहल है जिसे यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (USIBC) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
2. यह सर्कुलर इकोनॉमी प्रौद्योगिकियों तथा समाधानों पर काम करने वाले स्टार्टअप एवं छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों पर केंद्रित है।

PIB, AIR, PTI करेंट अफेयर्स वनलाइनर

राष्ट्रीय परिदृश्य

- हर बच्चे के लिए हर अधिकार' (Every Right for Every Child) अभियान का उद्देश्य क्या है?
  - **छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना**
- हाल ही में भारत के किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन (मैदानी क्षेत्र) में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया है?
  - **उत्तर प्रदेश**
- जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा ने रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जिसे "कॉलेज ऑन व्हील्स" के नाम से भी जाना जाता है?
  - **ज्ञानोदय एक्सप्रेस**
- तीर्थयात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास में किस राज्य ने पर्यटन माइक्रोसाइट्स की एक श्रृंखला के शुभारंभ ताकि राज्य की प्रचुर विरासत को उजागर किया जा सके? - **केरल**
- नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) के 42वें संस्करण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस मंत्रालय को आईआईटीएफ 2023 में विशेष प्रशंसा पदक से सम्मानित किया गया है? - **विद्युत मंत्रालय को**

विरासत एवं संस्कृति

- कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले और उडुपी के तटीय जिलों और केरल के कासरगोड एक क्षेत्र में किस पशु दौड़ का आयोजन किया जाता है? - **कंबाला दौड़**
- ओडिशा के कटक में किस ऐतिहासिक महोत्सव का प्रारम्भ कटक में महानदी के गडगड़िया घाट पर आयोजित किया गया है? - **बाली यात्रा**
- 9 नवंबर, 2023 को वांगला महोत्सव (Wangala Festival) का आयोजन किस राज्य में किया गया जो गारो समुदाय (Garo community) का एक लोकप्रिय त्योहार है? - **मेघालय**
- केरल के अग्रणी किस मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में स्थान हासिल करके वैश्विक प्रशंसा हासिल की है?
  - **रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म (आरटी) मिशन**
- 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें नागालैंड की पकवान, लोकनृत्य और कहानियां आदि संस्कृति के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते है?
  - **हॉर्नबिल महोत्सव**
- मंगलुरु के मांड शोभन के सहयोग से कुंडापुरा के कार्वाल्हो परिवार द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'कलाकार पुरस्कार' के 19वें संस्करण का पुरस्कार किस प्रमुख कोंकणी गायक, गीतकार और संगीतकार को दिया गया है? - **अपोलिनारिस डिसूजा**
- महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी पार्श्व गायक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेश ईश्वर वाडकर को 2023 के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? - **गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार**

आर्थिक परिदृश्य

- 4 नवंबर, 2023 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (NTPC Renewable Energy Limited - NTPC REL) द्वारा किस स्थान पर दयापार पवन परियोजना नामक 50 मेगावाट पवन फार्म परियोजना के वाणिज्यिक संचालन को प्रारंभ कर दिया है? - **गुजरात के कच्छ**
- माइक्रोसॉफ्ट ने किस महिला को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर (जीडीसी) लीडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की, जो इंडस्ट्री सॉल्यूशंस डिलीवरी और व्यापक माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर एंड पार्टनर सॉल्यूशंस (एमसीएपीएस) संगठन का एक हिस्सा है? - **अपर्णा गुप्ता**
- हाल ही किस कंपनी ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में पहले ह्यूमनॉइड रोबोट डपां' को नियुक्त किया है। में घोषणा की है? - **पोलिश रम कंपनी डिक्टाडोर**
- भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना आधिकारिक ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की है?
  - **महेंद्र सिंह धोनी**

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

- भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 14वां संस्करण, जिसे "वज्र प्रहार 2023" किस स्थान पर आयोजित की गई?
  - **उमरोई, मेघालय**
- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस कुशल और समर्पित कानूनी पेशेवर महिला को संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है?
  - **शकुंतला एल भाया**
- एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने किस अभिनेता को 2024 में 96वें अकादमी पुरस्कारों के मेजबान बनाया गया है? - **जिमी किमेल को**
- भारत-बांग्लादेश की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण बोंगोसागर-23 व समन्वित गश्ती का पांचवां संस्करण सात से नौ नवंबर तक किस समुद्री क्षेत्र में आयोजित किया?
  - **बंगाल की खाड़ी में**

पर्यावरण एवं जैव विविधता

- संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, 2022 में मीथेन की सांद्रता बढ़कर कितनी हो गई है?
  - **1,923 भाग प्रति बिलियन (Parts per Billion)**